साप्ताहिक

आरएनआई न. :- जेकेएचआईएन/25/ए0631

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी • वर्ष: 2 • अंक: 20 • कठुआ, शनिवार 16 मई , 2026 • पृष्ठ: 16 • मूल्य: 5 रूपए

प्रधानमंत्री मोदी ने काफिले का आकार कम किया भाजपा के मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ईंधन कम इस्तेमाल करने की उनकी अपील का पालन किया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफ़िले का साइज़ काफ़ी कम कर दिया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने फ़्यूल की खपत कम करने और समझदारी से खर्च करने की अपील की थी, जिससे कई ठश्रच मुख्यमंत्रियों और दूसरे नेताओं ने भी ऐसे ही कदम उठाए।

ऑफिशियल सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील कम खर्च करने की नहीं, बल्कि फ्यूल की खपत कम करके, इम्पोर्टेड सामान पर डिपेंडेंस कम करके और फॉरेन–करेंसी–इंटेंसिव सर्विसेज़ को समझदारी से खर्च करने की है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मोदी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेलफेयर खर्च या सब्सिडी में कोई कटौती नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री के हाल के घरेलू दौरों में उनके काफ़िले में कमी की गई। सूत्रों ने बताया कि ैच्ळ

प्रोटोकॉल के अनुसार ज़रूरी सुरक्षा चीज़ों को बनाए रखते हुए यह कमी की गई।

मोदी के भाषण के तुरंत बाद गुजरात और असम में उनके काफिले का साइज़ कम कर दिया गया। भाषण में उन्होंने इंपोर्ट पर खर्च कम करने के लिए कई उपाय सुझाए थे।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जहां तक हो सके, उनके काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल की जाएं, बिना कोई नई खरीदारी किए।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि फ्यूल बचाने, जहाँ तक हो सके वर्क–फ़्रॉम–होम अपनाने और ऐसे फॉरेन–एक्सचेंज आउटफ़्लो को कम करने की मोदी की अपील ष्कठोरता के उपायष् नहीं थे, जिनका नेगेटिव इकोनॉमिक मतलब हो।

उन्होंने कहा कि ष्ऑस्टेरिटीष् का मतलब आम तौर पर बजट में कटौती, सरकारी खर्च में कमी, सब्सिडी में कमी और फिस्कल सख्ती होता है।

लेकिन सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील कम खर्च करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह फ्यूल की खपत कम करके, इम्पोर्टेड सामान पर निर्भरता कम करके और फॉरेन–करेंसी–इंटेंसिव सर्विसेज़

■ शेष पेज 2...

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन के समर्थन पर भारत ने कहा, यह जिम्मेदार देशों को सोचना चाहिए

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : भारत ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के सपोर्ट की रिपोर्ट्स से वही बात साबित होती है जो पहले से पता थी और ज़िम्मेदार देशों को इस पर सोचना चाहिए कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की कोशिशों को सपोर्ट करने से उनकी ग्लोबल पहचान पर क्या असर पड़ेगा।

नई दिल्ली की यह टिप्पणी चीन के इस कन्फर्मेशन के कुछ दिनों बाद आई है कि उसने भारत के साथ चार दिन की मिलिट्री लड़ाई के दौरान पाकिस्तान को ऑन–साइट टेक्निकल सपोर्ट दिया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का एक सटीक, टारगेटेड और सोच–समझकर किया गया जवाब था। उन्होंने अपनी वीकली मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ष्हमने ये रिपोर्ट देखी हैं जो पहले से पता चली बातों

■ शेष पेज 2...

सीमावर्ती गांवों के लोग राष्ट्र निर्माण में असाधारण भूमिका निभाते हैं : एलजी मनोज सिन्हा

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू–कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि बॉर्डर के गांवों के लोगों पर देश की सेवा करने की ष्बहुत बड़ी ज़िम्मेदारीष् है।

सिन्हा ने बारामूला के उरी इलाके के उरन बोवा गांव का दौरा किया और केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया और एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ने बॉर्डर के गांवों को देश की मुख्यधारा के करीब ला दिया है, और कहा कि सरकार उन्हें इनक्लूसिव डेवलपमेंट के सिंबल में बदलने के लिए

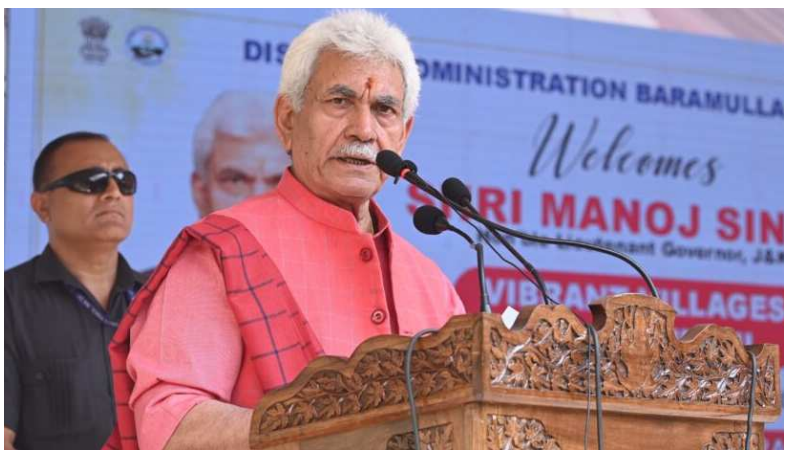

कमिटेड है। उन्होंने कहा, हमारे बॉर्डर के गांवों के लोग, खासकर किसान, युवा और महिलाएं, देश की सेवा करने की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के मुताबिक, वाइब्रेंट

■ शेष पेज 2...

कठुआ-बिलावर-भद्रवाह रेल लाइन की मांग तेज

विधायक राजीव जसरोटिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर परियोजना को जल्द मंजूरी देने की उठाई मांग

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : जसरोता से बीजेपी विधायक राजीव जसरोटिया ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कठुआ–बिलावर–बशोली–बनी–भद्रवाह रेल कॉरिडोर को जल्द मंजूरी देने की मांग की।

राजीव जसरोतिया ने कहा कि यह रेल परियोजना जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना करीब 185

किलोमीटर लंबी होगी और इसे पांच चरणों में पूरा करने की योजना है।

प्रस्ताव के अनुसार पहले चरण में अजीजपुर (माधोपुर, पंजाब) से कठुआ और फिर बिलावर तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। आगे चलकर यह लाइन मनवाल, बशोली, बनी और भद्रवाह तक पहुंचेगी।

विधायक ने बताया कि इस रेल लाइन के बनने से कठुआ से बिलावर की दूरी काफी कम हो जाएगी। इसके लिए बालासुंदरी माता मंदिर के पास पहाड़ के नीचे सुरंग बनाने की योजना भी है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पर्यटन, व्यापार, रोजगार और औद्योगिक विकास को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही दूर–दराज पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी।

राजीव जसरोतिया ने कठुआ शहर में नया रेलवे स्टेशन बनाने की मांग भी रखी। उन्होंने

■ शेष पेज 2...

कठुआ में पेयजल संकट जल्द दूर करने की मांग

विधायक डॉ. भारत भूषण ने जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा से मुलाकात कर उठाए मुद्दे

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ/श्रीनगर। भारत भूषण ने श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में जावेद अहमद राणा से मुलाकात कर कठुआ क्षेत्र में पेयजल की समस्या

■ शेष पेज 2...

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

शेष पेज 1 से.....

प्रधानमंत्री मोदी ने...

को कम करके समझदारी से खर्च करने के बारे में है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई यूनियन कैबिनेट की मीटिंग के दौरान, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने मंत्रियों से कहा कि उन्हें वेस्ट एशिया संकट को देखते हुए कॉस्ट–कटिंग पर ध्यान देना चाहिए और जान–बूझकर रिसोर्स का खर्च कम करना चाहिए।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से अपने काफिले का साइज़ और विदेश दौरे कम करने की भी अपील की, जिसके बाद कई मंत्रियों ने इस बारे में कदम उठाने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री की अपील से सीख लेते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने और मंत्रियों के साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या में तुरंत 50 परसेंट की कमी करने का निर्देश दिया है।

आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री की समझदारी से खर्च करने की अपील को अपनाने की भी अपील की।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि वह अपने काफिले के लिए कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और अपने मंत्री साथियों से भी ऐसा ही करने को कहा है। उन्होंने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

यादव ने कहा, ष्अगले आदेश तक, सुरक्षा के नज़रिए से मेरे काफिले में कम से कम गाड़ियां होंगी, और कोई गाड़ी रैली नहीं होगी। सभी मंत्री भी यात्रा करते समय कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे।ष

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों की सरकारी गाड़ियों की लिमिट तय कर दी है।

उन्होंने दिल्ली के लोगों से कारपूलिंग अपनाने और प्राइवेट गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने की भी अपील की।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी निर्देश दिया कि उनके काफिले का इस्तेमाल कम से कम किया जाए । उन्होंने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी इसी तरह के तरीके अपनाने के निर्देश दिए।

महाराष्ट्र सरकार ने सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पहले मंजूरी लेने का निर्देश दिया है। फडणवीस ने ऑफिशियल यात्रा के लिए एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने से पहले यह बात कही।

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनर्जी बचाने और सस्टेनेबल गवर्नेंस की दिशा में एक कदम के तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनाई है।

शिव के सभी मंत्री ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि शिवसेना को गैर–ज़रूरी यात्रा कम करने और ऑफिशियल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की संख्या कम करने की भी सलाह दी गई है ।

उन्हें इन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने और फ्यूल बचाने, एनर्जी एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट की ज़िम्मेदारी में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने घोषणा की कि वे राज्य के अंदर हेलीकॉप्टर और फ्लाइट्स के बजाय ट्रेनों, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करेंगे, साथ ही फ्यूल बचाने के लिए सरकारी गाड़ियों का साइज़ भी कम करेंगे।

गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने भी अमेरिका की अपनी तय यात्रा कैंसिल कर दी।

बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने घोषणा की है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है और वे सिर्फ ज़रूरी होने पर ही ऑफिशियल यात्रा करेंगे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी सरकार राज्य पर पश्चिम एशिया संघर्ष के असर को कम करने के लिए दो दिनों के अंदर एहतियाती कदम उठाएगी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने कहा कि उन्होंने अपने काफिले का साइज़ कम कर दिया है और भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर खास ध्यान दिया जाएगा।

हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता को लोक सभा में शामिल किया गया उन्होंने एक श्फ्यूल कंज़र्वेशन ज़ोनश बनाने की बात कही और यूनिवर्सिटीज़ से कंज़र्वेशन मूवमेंट को लीड करने की अपील की।

पश्चिम एशिया में संकट के बीच, मोदी ने रविवार को पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल कम करने, शहरों में मेट्रो रेल सर्विस का इस्तेमाल करने, कारपूलिंग करने, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने, पार्सल लाने–ले जाने के लिए रेलवे सर्विस का इस्तेमाल करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए घर से काम करने का सुझाव दिया।

ऑपरेशन सिंदूर में...

को सही साबित करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए टेररिस्ट हमले का एक सटीक, टारगेटेड और सोचा–समझा जवाब था, जिसका मकसद पाकिस्तान से और उसके इशारे पर चल रहे स्टेट–स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना था।ष

जायसवाल ने कहा, ष्जो देश खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की कोशिशें को सपोर्ट करने से उनकी रेप्युटेशन और स्टैंडिंग पर असर पड़ता है या नहीं।

चीन की ऑफिशियल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले हफ़्ते चीन ने पहली बार कन्फर्म किया कि उसने लड़ाई के दौरान पाकिस्तान को ऑन–साइट टेक्निकल सपोर्ट दिया था।

चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर ब्ब्ज्ट ने एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ़ चाइना के चेंगदू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर झांग हेंग का इंटरव्यू दिखाया।

।टप्ब चीन के एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल डिज़ाइन का एक मुख्य डेवलपर है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ब्ब्ज्ट के हवाले से बताया कि झांग ने पिछले साल मई में चार दिन के युद्ध के दौरान पाकिस्तान को टेक्निकल सपोर्ट दिया था।

पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स चीन में बने श्र–10ब् जेट्स का एक बेड़ा चलाती है, जिसे ।टप्ब की सब्सिडियरी बनाती है।

इंडियन आर्मी स्टाफ (स्ट्रेटेजी) के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने 7 मई को पाकिस्तान और चीन के बीच षमिलीभगतष के बारे में बात की।

उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था, ष्सच तो यह है कि पाकिस्तान और चीन के अपने शब्दों में, उनका रिश्ता समुद्र से भी गहरा है, पहाड़ों से भी ऊंचा है, यह तो तय है। यह भी तय है कि पाकिस्तान के 80 परसेंट मिलिट्री इक्विपमेंट चीन के हैं।ष

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में, भारत ने पिछले साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की गई थी, जिसमें कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए थे।

इन हमलों से तनाव तेज़ी से बढ़ गया और पाकिस्तान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए, हालांकि भारतीय सेना ने उनमें से ज़्यादातर को नाकाम कर दिया। दोनों पक्षों के सेना अधिकारियों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत के बाद 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के साथ दुश्मनी खत्म हुई।

सीमावर्ती गांवों के...

विलेज प्रोग्राम चुने हुए बॉर्डर गांवों में इनक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इसके मेन एरिया में चार खास एरिया हैं — हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी, घरों में बिजली, टेलीकॉम कनेक्टिविटी और टेलीविज़न कनेक्टिविटी।

ष्मुझे सच में विश्वास है कि सड़कें नई संभावनाओं को खोलती हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आने वाले सभी 18 गांव अब हर मौसम में चलने वाली सड़कों से जुड़ गए हैं। बारामूला के सभी 83 बॉर्डर गांवों को जोड़ने का काम तेज़ कर दिया गया है, और बहुत जल्द, जम्मू और कश्मीर का हर बॉर्डर गांव आर्थिक मुख्यधारा में शामिल हो जाएगा और देश के दूसरे खास शहरों से जुड़ जाएगा।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, ष्2019 से पहले, उन 18 स्ट्रेटेजिक रूप से ज़रूरी गांवों में टेलीकॉम और डिजिटल कवरेज 40 परसेंट से कम था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमने इन ज़रूरी जगहों पर 100 परसेंट 4ळ और 5ळ कनेक्टिविटी पक्की की है।ष

सिन्हा ने बॉर्डर के गांवों के लोगों को भरोसा दिलाया कि डिजिटल क्रांति शहर की सीमा पर नहीं रुकेगी और प्रशासन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और हर बॉर्डर के गांव तक भरोसेमंद मोबाइल और इंटरनेट सर्विस देने के लिए कमिटेड है।

उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, और एक खुशहाल समाज के लिए बॉर्डर इलाकों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने दोहराया कि एडमिनिस्ट्रेशन तीन खास पैरामीटर पर काम कर रहा है — लिटरेसी रेट में सुधार, इकोनॉमिक ग्रोथ पक्का करना, और उरण बोवा जैसे गांवों के युवाओं के लिए लाइवलीहुड जेनरेशन के मौके देना।

सिन्हा ने कहा, ष्बॉर्डर इलाकों में युवाओं और महिलाओं के पास अब सेल्फ–एम्प्लॉयमेंट के मौके हैं, एजुकेशन का बढ़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अगली पीढ़ी को वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, और बॉर्डर टूरिज्म, जो खेती और उससे जुड़े सेक्टर में एक नई क्रांति है, ने सभी 18 ज़रूरी गांवों में खुशहाली लाई है।ष

उन्होंने अलग–अलग सेक्टर में 94 करोड़ रुपये के अलग–अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–प्प के तहत 83 गांवों में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी किए।

कठुआ–बिलावर–भद्रवाह...

कहा कि मौजूदा रेलवे स्टेशन शहर से दूर होने के कारण लोगों को परेशानी होती है।

इसके अलावा उन्होंने जसरोता क्षेत्र में कई जगह रेलवे अंडरपास बनाने की मांग उठाई ताकि लोगों और स्कूली बच्चों को सुरक्षित आवा. जाही मिल सके।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी मांगों को ध्यान से सुना और कहा कि प्रस्तावों पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जाएगा।

कठुआ में पेयजल...

को प्रमुखता से उठाया।

विधायक ने बताया कि कठुआ शहर और विधानसभा क्षेत्र के कांडी इलाकों में गर्मियों के दौरान पानी की भारी कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने की तुरंत जरूरत है। डॉ. भारत भूषण ने मंत्री को यह भी बताया कि जल जीवन मिशन के तहत कई योजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें फिजिकली और फाइनेंशियली पूरा कर जल्द चालू किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके।

उन्होंने मंत्री को कठुआ, लखनपुर और नगरी कस्बों के लिए स्वीकृत लगभग 55 करोड़ रुपये की अमृत स्कीम 2.0 का शिलान्यास करने के लिए भी आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से वर्ष 2040 की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखते हुए बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

भारत गुरूवार से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग होस्ट करेगा; वेस्ट एशिया संकट, एनर्जी सिक्योरिटी टॉप एजेंडा में

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : गुरुवार से भारत की मेज़बानी में होने वाली ठत्प्ब् विदेश मंत्रियों की दो दिन की मीटिंग में पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर इसके असर पर चर्चा होने की उम्मीद है।

हालांकि तेहरान ने विदेश मंत्री अब्बास अराघची के आने की पुष्टि की है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि अगर इलाके में अचानक तनाव बढ़ता है तो उनके प्लान में बदलाव हो सकता है।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली कॉन्क्लेव में शामिल नहीं होंगे और ै प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तीन दिन के स्टेट विज़िट के लिए बीजिंग में ही रहेंगे, जो ठत्प्ब् मीटिंग के साथ हो रहा है।

बीजिंग ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत में चीन के राजदूत शी फेइहोंग वांग की ओर से बैठक में शामिल होंगे। कॉन्क्लेव के पहले दिन ठत्प्ब् के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने बताया कि रूस के सर्गेई लावरोव समेत कई ठत्प्ब् सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में होने वाली मीटिंग में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। ब्रिक्स का चेयरमैन होने के नाते, भारत सितंबर में ग्रुप के सालाना समिट से पहले विदेश मंत्रियों की मीटिंग होस्ट कर रहा है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या विदेश मंत्रियों की मीटिंग में पश्चिम एशिया में संघर्ष पर आम सहमति वाला बयान बन पाता है।

ईरान पर ै–इज़राइल युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेदों की वजह से, पिछले महीने ग्रुप के डिप्टी विद.`श मंत्रियों और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका पर स्पेशल दूतों की मीटिंग के दौरान, इस लड़ाई पर आम सहमति बनाने की भारत की कोशिशें रुक गईं।

यूनाइटेड अरब अमीरात और ईरान के बीच मतभेदों की वजह से इस झगड़े पर कोई आम राय नहीं बन पाई। न।म में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के कथित हमलों को लेकर हाल के हफ्तों में दोना.`पड़ोसी देशों के बीच कहासुनी हुई है।

ऊपर बताए गए सूत्रों ने बताया कि ठत्प्ब् विदेश मंत्रियों की मीटिंग में वेस्ट एशिया विवाद और एनर्जी सप्लाई पर इसके असर पर खास तौर पर बात होने की उम्मीद है।

वेस्ट एशिया में लड़ाई बढ़ने के बाद, ईरान ने भारत से, जो अभी ठत्प्ब् का चेयरमैन है, ईरान के खिलाफ यूएस–इज़राइल की दुश्मनी को रोकने के लिए अपनी इंडिपेंडेंट भूमिका का इस्तेमाल करने की अपील की। ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य को लगभग ब्लॉक करने के बाद दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक पतली शि. पिंग लेन है।

आईसीसी प्रौद्योगिकी सम्मेलन में राहुल साहनी ने साझा किए भविष्य के विजन

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : मुंबई में आयोजित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के विश्व प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2026 में जम्मू चौप्टर के अध्यक्ष राहुल साहनी ने वैश्विक क्षमता केंद्रों और नई पीढ़ी की तकनीकी गतिशीलता एवं अवसंरचना से जुड़े महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करते हुए भारत की तकनीकी प्रगति, औद्योगिक विस्तार और नवाचार आधारित विकास पर विस्तार से अपने विचार रखे। दो दिवसीय यह सम्मेलन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में "मेक इन इंडिया के लिए प्रौद्योगिकी" विषय के तहत आयोजित किया गया, जिसमें देशभर से उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्यमियों, नवाचारकर्ताओं और सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राहुल साहनी ने "वैश्विक क्षमता केंद्र पारिस्थितिकी तंत्र रू वर्ष 2040 और उससे आगे की नई कल्पना" तथा "नई पीढ़ी की तकनीकी गतिशीलता और अवसंरचना" विषयों पर आयोजित सत्रों की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत तेजी से वैश्विक तकनीकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत प्रतिभा आधार, उन्नत डिजिटल अवसंरचना, नवाचार आधारित विकास और सरकार की प्रगतिशील नीतियों ने भारत को वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना दिया है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक क्षमता केंद्र अब केवल सेवा क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास, उन्नत विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा और वैश्विक व्यापार परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राहुल साहनी ने कहा कि भारत में युवाओं की प्रतिभा, तकनीकी दक्षता और नवाचार की क्षमता ने देश को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में वैश्विक क्षमता केंद्र भारत की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

नई पीढ़ी की तकनीकी गतिशीलता और अवसंरचना पर बोलते हुए राहुल साहनी ने कहा कि भारत का परिवहन और अवसंरचना क्षेत्र अभूतपूर्व विस्तार के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स, रेलवे, विद्युत आधारित परिवहन और स्मार्ट अवसंरचना में हो रहे निवेश से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। उन्होंने हरित ऊर्जा और टिकाऊ विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि भविष्य की तकनीकें भारत को वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनाने में मदद करेंगी।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता महाराष्ट्र सरकार के उद्योग, निवेश एवं सेवा विभाग के प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बलगन ने की। इस अवसर पर भारत सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के राष्ट्रीय निदेशक अभिजीत सिन्हा, अटल नवाचार मिशन के प्रबंध निदेशक दीपक बागला तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एल.सी. मंगल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के महानिदेशक, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय समिति अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वैश्विक क्षमता केंद्र पारिस्थितिकी तंत्र विषय पर आयोजित सत्र में कई प्रतिष्ठित उद्योग विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इनमें जॉनसन कंट्रोल्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उपाध्यक्ष एवं एशिया–प्रशांत समाधान प्रमुख शिवकुमार गणपति, सोनाटाइप इंडिया के केंद्र प्रमुख अभिषेक चौहान, द नोआ एआई के संस्थापक आकाश सुरेका, आईडीओएक्स पीएलसी इंडिया के कंट्री डायरेक्टर कैलाश मैसेकर तथा ट्रांसयूनियन एशिया के मुख्य रणनीति अधिकारी मयूर कपूर शामिल रहे। विशेषज्ञों ने भारत में तकनीकी नवाचार, वैश्विक निवेश और डिजिटल परिवर्तन की संभावनाओं पर चर्चा की।

सम्मेलन के दौरान ऊर्जा एवं हरित प्रौद्योगिकी, खनन 5.0, रक्षा, एयरो एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, वित्तीय तकनीक, कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तकनीक, शिक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट जल प्रबंधन, उद्योग 4.0 और मेक इन इंडिया के लिए भारत की तकनीकी प्रतिस्पर्धा जैसे कई विषयों पर विस्तृत सत्र आयोजित किए गए। इन चर्चाओं में तकनीकी विकास के साथ–साथ औद्योगिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर विचार–विमर्श हुआ।

कार्यक्रम में उद्योगों के बीच व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए विशेष नेटवर्किंग सत्र भी आयोजित किए गए। इसके अलावा आईसीसी तकनीकी उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह और विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम भी हुए। सम्मेलन ने उद्योग जगत, सरकार और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराया।

सम्मेलन के समापन अवसर पर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने देश में तकनीकी प्रगति, नवाचार आधारित औद्योगिक विकास और भारत को वैश्विक विनिर्माण एवं तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में तेजी से बढ़ती तकनीकी क्षमता और युवा शक्ति देश को आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की दिशा में आगे ले जाएगी।

अमरनाथ यात्रा सेवाओं में स्थानीय लोगों को मिले प्राथमिकता : शिवसेना

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : शिवसेना (उद्धव बाला. साहेब ठाकरे) की जम्मू–कश्मीर इकाई ने सोमवार को सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन ठवंतक से आगामी श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सभी सेवाओं और ठेकों में स्थानीय युवाओं, व्यापारियों एवं छोटे सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता देने की मांग की।

पार्टी के प्रदेश प्रमुख मनीश साहनी ने संवाददाताओं से कहा कि अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि जम्मू–कश्मीर की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है।

इस यात्रा से पर्यटन, परिवहन, होटल उद्योग, घोड़ा सेवा, पिट्ठू, पालकी, टेंट व्यवसाय और छोटे व्यापार से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका चलती है।

उन्होंने कहा कि "ऑपरेशन सिंदूर" के बाद प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। होटल, टैक्सी, हाउसबोट, दुकानदारों और स्थानीय बाजारा. का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे समय में अमरनाथ यात्रा जम्मू–कश्मीर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का बड़ा माध्यम बन सकती है।

साहनी ने मांग की कि यात्रा से संबंधित टेंडर, परमिट और अस्थायी लाइसेंस जारी करते समय स्थानीय लोगों के लिए स्पष्ट प्राथमिकता नीति लागू की जाए। उन्होंने कहा कि घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, टेंट, ट्रांसपोर्ट, कैंप और अन्य सेवाओं के कार्य किसी एक बड़े ठेकेदार या बाहरी एजेंसी तक सीमित न रखे जाएं, बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ छोटे स्थानीय ठेकेदारों, युवाओं और सेवा प्रदाताओं में समान रूप से बांटे जाएं, ताकि यात्रा का लाभ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित न रहकर हजारों स्थानीय परिवारों तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से छोटे व्यापारियों और स्थानीय ठेकेदारों की यह शिकायत रही है कि उन्हें नजर. अंदाज कर बड़े ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे स्थानीय लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए, क्योंकि यात्रा से जुड़े आर्थिक अवसरों पर सबसे पहला अधिकार स्थानीय लोगों का है।

साहनी ने कहा, "आतंकवाद और कठिन परिस्थितियों के दौर में भी स्थानीय लोगों ने ही अमरनाथ यात्रा को सुचारु रूप से जारी रखने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए सरकार और श्राइन बोर्ड को स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।" उन्होंने जम्मू को केवल 'ट्रांजिट प्वाइंट' तक सीमित रखने के बजाय धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की भी मांग की, ताकि श्रद्धालु यहां अधिक समय व्यतीत करें और स्थानीय व्यापार तथा पर्यटन उद्योग को मजबूती मिले।

सुरक्षित रहे बाबा बर्फानी का पवित्र स्वरूप

साहनी ने यात्रा अवधि के दौरान बाबा बर्फानी के पवित्र हिम स्वरूप के समय से पहले अंतर्ध्यान होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गुफा परिसर में अत्यधिक भीड़ और अनावश्यक हस्तक्षेपों से प्राकृतिक वातावरण प्रभावित होता है। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन और नियंत्रित भीड़ व्यवस्था के माध्यम से पूरे यात्रा काल तक पवित्र हिम शिवलिंग के स्वरूप को सुरक्षित बनाए रखने की मांग की।

जम्मू में 14 लाख कनाल और कश्मीर में 3 लाख कनाल सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा : सरकारी डेटा

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू–कश्मीर में लैंड माफिया ने 17 लाख कनाल से ज़्यादा सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। जम्मू डिवीज़न में यह 14 लाख कनाल से ज़्यादा है, जो कश्मीर डिवीज़न में दर्ज आँकड़ों से तीन गुना ज़्यादा है। वहीं, राजौरी ज़िला सभी 20 ज़िलों में सबसे ऊपर है। यह जानकारी सरकारी डेटा में दी गई है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू–कश्मीर में करीब 17,27,247 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा करके रखी गई एंट्री को रेवेन्यू रिकॉर्ड से हटा दिया गया।

इसमें कहा गया है कि कुल में से जम्मू संभाग में 14,00,051 कनाल और पांच मरला अतिक्रमित सरकारी भूमि थी, जिसकी प्रविष्टियां राजस्व रिकॉर्ड से हटा दी गईं, जबकि कश्मीर संभाग में 3,27,199 कनाल दर्ज की गईं। डेटा से क्षेत्रीय अंतर साफ़ पता चला, जिसमें जम्मू डिवीज़न के सात ज़िलों में हर एक में एक लाख कनाल से ज़्यादा सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा है, जबकि दो ज़िलों – राजौरी और रियासी – में यह आंकड़ा दो लाख कनाल को पार कर गया है।

इसके उलट, कश्मीर डिवीज़न के 10 ज़िलों में से किसी में भी एक लाख कनाल से ज़्यादा कब्ज़ा दर्ज नहीं हुआ। घाटी में सिर्फ़ बारामूला और कुपवाड़ा में ही 50,000 कनाल का आंकड़ा पार हुआ है, ऐसा कहा गया।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि जम्मू और श्रीनगर, दोनों राजधानी जिलों में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क था।

जम्मू जिले में 1,45,487 कनाल और छह मरला ज़मीन पर कब्ज़ा है, जबकि श्रीनगर में 13,862.95 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा है, जिससे पता चलता है कि अकेले जम्मू जिले में श्रीनगर की तुलना में दस गुना ज़्यादा सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा है।

सरकारी डेटा के मुताबिक, राजौरी ज़िला जम्मू–कश्मीर में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े के मामले में सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला बन गया है, जहाँ 2.73 लाख कनाल ज़मीन पर ज़मीन हड़पने वालों का गैर–कानूनी कब्ज़ा है। राजौरी 2,73,848 कनाल और 12 मरला सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा होने के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, इसके बाद रियासी 2,26,857 कनाल और छह मरला और रामबन 1,73,832 कनाल के साथ दूसरे नंबर पर है। जम्मू ज़िले में 1,45,487 कनाल और छह मरला ज़मीन पर कब्ज़ा है, जबकि कठुआ में 1,30,403 कनाल और 1.5 मरला ज़मीन पर कब्ज़ा है।

आंकड़ों के अनुसार, उधमपुर और पुंछ में भूमि क्रमशः 1,19,822 कनाल और आठ मरला तथा 1,11,133 कनाल और 16 मरला के साथ एक लाख कनाल का आंकड़ा पार कर गई।

डोडा में 91,957 कनाल और पांच मरला ज़मीन पर कब्ज़ा है, इसके बाद सांबा ज़िले में 74,196 कनाल और तीन मरला ज़मीन पर कब्ज़ा है, जबकि किश्तवाड़ में 52,513 कनाल और 7.5 मरला ज़मीन पर कब्ज़ा है।

डेटा से पता चला कि कश्मीर डिवीज़न में, बारामूला में सबसे ज़्यादा 81,327.65 कनाल ज़मीन हटाई गई, इसके बाद जम्मू डिवीज़न के सांबा में 74,196 कनाल और तीन मरला, कुपवाड़ा में 52,698.1 कनाल और किश्तवाड़ में 52,513 कनाल और 7.5 मरला ज़मीन हटाई गई।

इसमें कहा गया है कि पुलवामा में 42,730.8 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा है, इसके बाद अनंतनाग में 36,984 कनाल, बडगाम में 21,775.55 कनाल और बांदीपोरा में 20,925.65 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा है।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि शोपियां में 19,034.85 कनाल, गंदेरबल में 19,005.2 कनाल, कुलगाम में 18,853.75 कनाल और श्रीनगर में 13,862.95 कनाल अतिक्रमण हटाये गये।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

'नई विनिवेश नीति : केंद्रीय उद्यमों की 74: हिस्सेदारी बेचने की साजिश'

आलेख : स्वदेश देव रॉय, अनुवाद : संजय पराते

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर हो रहे विनाशकारी हमलों के इस मौजूदा दौर में, हमें केंद्र की मौजूदा राजग सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र को नीचा दिखाने वाली नीति के पीछे के आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझना होगा।

'पूंजीवाद का व्यवस्थागत संकट'

निजीकरण के इस आक्रामक अभियान के आर्थिक पहलू को, पूंजीवाद के उस लगातार गहराते जा रहे व्यवस्थागत संकट के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए, जिसने पूरे पूंजीवादी विश्व को अपनी जकड़ में ले लिया है। हमेशा की तरह, मौजूदा आर्थिक संकट में भी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ही सरकार के सबसे आसान शिकार हैं, ताकि संकट से निपटने के लिए संसाधन जुटाए जा सकें। आर्थिक संकट को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को बेच देने की इस कवायद को बिल्कुल सही ही यह नाम दिया गया है कि ष्लोकर का वेतन चुकाने के लिए घर के कीमती बर्तन बेच देना।ष

निजीकरण की विनाशकारी मुहिम के पीछे के राजनीतिक और वैचारिक पहलुओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति राजीव कुमार के शब्दों में मिलती है, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना, केवल राजस्व जुटाने का एक माध्यम भर नहीं है, 'यह निजी क्षेत्र को अधिक जगह और अवसर देने का भी एक माध्यम है।' अब सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सर्वोच्च स्तर पर मौजूद राजनीतिक नेतृत्व (यानी प्रधानमंत्री) ने भी यह स्पष्ट कर दिया है।

इसके अलावा, इस राजनीतिक मिशन का उद्देश्य निजी पूंजी कृ चाहे वह विदेशी हो या घरेलू कृ को यह संकेत देना है कि मोदी सरकार निजी पूंजी के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना है, और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उसकी नीति श्शून्य सहनशीलताश की है। यही नहीं, यह सरकार स्पष्ट रूप से नव–उदारवाद के सिद्धांत के प्रति समर्पित है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी अवशेष के भी सख्त खिलाफ है। इसके साथ ही, इसका मकसद यह प्रदर्शित करना है कि मोदी सरकार पूरी तरह से निजी क्षेत्र के लिए समर्पित है और निष्कर्षतः सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध है।

नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग को समाप्त करना और उसकी जगह कुख्यात श्नीति आयोगश का गठन करना भी नव–उदारवादी विचारधारा से ही प्रेरित है। ऐसे अकाट्य तथ्य और आँकड़े मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि 1951 से लेकर अब तक भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की योजना बनाने, उन्हें वित्त पोषित करने और उनके निर्माण में कृ विशेषकर बुनियादी रणनीतिक क्षेत्रों में कृ योजना आयोग ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

''गई गुजरी नई विनिवेश नीति''

वर्तमान सरकार का यह हताश इरादा है कि वह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पूरी तरह से निजीकरण कर देगी। यह 'नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति' दस्तावेज़ के इस उद्धरण से बिल्कुल स्पष्ट है रू रणनीतिक क्षेत्र/गैर–रणनीतिक क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा, विलय किया जाएगा, उन्हें किसी अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ मिला दिया जाएगा, उनकी सहायक कंपनियाँ बनाई जाएँगी या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। 'उपर्युक्त रणनीतिक क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उपस्थिति केवल नाम मात्र की ही रखी जाएगी।'

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के 74: शेयर निजी व्यवसायों को बेचने के उद्देश्य से, वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत 2025–26 के 'आर्थिक सर्वेक्षण' में इस राष्ट्र–विरोधी 'निजीकरण परियोजना' को आगे बढ़ाने के लिए कई विनाशकारी कदम सुझाए गए हैं। सरकार कंपनी अधिनियम में संशोधन करेगी, जिसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 74: हिस्सेदारी बेचने के बाद भी, यदि उनके पास केवल 26: हिस्सेदारी बचती है, तो भी उन्हें श्सरकारी कंपनीश के रूप में ही परिभाषित किया जा सकेगा। अधि. नियम के मौजूदा प्रावधान के अनुसार, कोई भी फर्म तभी श्सरक. ारी कंपनीश मानी जाती है, जब उसकी कम से कम 51: हिस्सेदारी सरकार के पास हो। यह सरकार की हताशा को दर्शाता है कृ यह देश की जनता को धोखा देने की कोशिश है, और साथ ही खुद को भी भ्रम में रखने जैसा है। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी यह जानता है कि किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा इक्विटी रखने वाला ही उसका असली मालिक होता है।

12–13 फरवरी, 2026 को, भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली एक संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति के क्रियान्वयन में तेज़ी लाने का आग्रह किया है। समिति ने कथित तौर पर कहा है कि इस नई नीति को राजकोषीय अनुशासन की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेकिन साथ ही यह भी टिप्पणी की कि इसके ठोस परिणाम अभी तक सुस्त रहे हैं ; इसलिए, नीतिगत लक्ष्यों और उनके क्रियान्वयन के बीच के अंतर को पाटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है!

इस बीच, पूरे देश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों की विशाल ज़मीन–जायदाद से पैसा कमाने के लिए, सरकार ने पहले ही एक खास ज़मीन–हथियाने वाली संस्था बना दी है, जिसका नाम है 'नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन' (एनएलएमसी)।

ज़ाहिर है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों की सबसे कीमती जमीन राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपला. इन–02 का मुख्य निशाना होगी। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन–02 के लिए चुने गए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ में हाईवे, रेलवे, सिविल एविएशन, बंद. रगाह, पेट्रोलियम, बिजली, कोयला खदानें, दूसरी खदानें, टेलीकॉम और पर्यटन आदि शामिल हैं।

इस संशोधित सार्वजनिक क्षेत्र नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 74: शेयर बेचने का मोदी सरकार का फ़ैसला, देश में सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। और निजीकरण की इस परियोजना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन–02 के तहत तैयार किया गया रोडमैप, घरेलू और विदेशी कृ दोनों ही तरह के निजी व्यापारिक दिग्गजों के लिए एक बड़ा फ़ायदा साबित होगा।

'राष्ट्रीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण पाइपलाइन नीति – 02'

राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन निस्संदेह एक पूरी तरह से राष्ट्र–विरोधी नीति है, जिसे मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से लाभदायक परिसंपत्तियों को, मोदी की पसंद के बड़े निजी व्यापारिक घरानों को सौंपने के लिए घोषित किया है। यह हस्तांतरण एक संदिग्ध तंत्र के माध्यम से किया जाएगा, जिसे किसी और ने नहीं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के विध्वंसक कृ नीति आयोग कृ ने तैयार किया है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपला. इन– 02 को मोदी सरकार की संशोधित सार्वजनिक नीति को साकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हालाँकि सरकार द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और पूँजीपति वर्ग के कलमघिस्सुओं द्वारा श्राष्ट्रीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण पाइपलाइनश (एनएमपी) के आर्थिक लाभों के बारे में कपटपूर्ण बातें कही जा रही हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि एनएमपी बड़े निजी कॉर्पोरेटोंकृ चाहे वे घरेलू हों या विदेशी कृ के लिए एक तोहफ़ा है। यह उन्हें बिना किसी निवेश के और बिना किसी प्रतीक्षा के, तत्काल मुनाफ़ा कमाने की सुविधा प्रदान करता है। जिन सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, वे मूल और रणनी. तिक प्रकृति की हैं ; इनका भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है, और इनके लिए बाज़ार भी पूरी तरह से सुनिश्चित है।

'केंद्रीय बजट 2025–26'

केंद्रीय बजट 2025–26 में एनएमपी 2.0 को शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि 2021 में घोषित पहली परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, दूसरी योजना को समर्थन देने के लिए नियामक और राजकोषीय उपायों को और बेहतर बनाया जाएगा। एमएनपी 2. 0 का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026 से 2030 के दौरान परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण से 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाना है। एनएमपी–02 के क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट और रोडमैप नीति आयोग द्वारा पहले ही तैयार और प्रकाशित किया जा चुका है।

आयोग के अनुसार, एनएमपी 1.0 ने अपने लक्ष्य का 89: हिस्सा हासिल किया है, जो कि 5.3 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। इस पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा, अधिक मुनाफ़ा कमाने वाली संपत्तियों को निजी क्षेत्र को आउटसोर्स करके जुटाया गया है।

एनएमपी–01 की तरह ही, एनएमपी 2.0 भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों की संपत्तियों के हस्तांतरण, उनके हिस्से की बिक्री, सुरक्षित नकद प्रवाह या रणनीतिक व्यावसायिक नीलामी के ज़रिए संपत्ति के मौद्रीकरण का सहारा लेगा। एनएमपी–02 के तहत पहचाने गए क्षेत्रों में हाईवे, कोयला खदानें, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, बंदरगाह और दूरसंचार शामिल हैं।

सरकार का दिवालियापन और हताशा इस चौंकाने वाले तथ्य से उजागर होता है कि एनएमपी–2.0 का ध्यान केवल मुख्य संपत्तियों पर ही होगा। विभिन्न मुख्य संपत्तियों में से, उन संपत्तियों पर ध्यान दिया जाएगा, जो वर्तमान में राजस्व कमा रही हैं या जिनकी सुविधाएं काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं और जिन्हें उचित रूप से बढ़ाया जाएगा। इसलिए, एनएमपी–01 की तरह ही, इस बार भी बेहतरीन ढंग से संचालित और मुनाफ़ा कमाने वाली सार्वजनिक इकाईयों को ही निशाना बनाया गया है।

'सकल राजस्व, शुद्ध लाभ और राजकोष में योगदान'

वित्त वर्ष 2023–24 की तुलना में, वित्त वर्ष 2024–25 में सकल राजस्व 36.08 लाख करोड़ रूपये से बढ़कर 37.01 लाख करोड़ रूपये हो गया। कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का शुद्ध लाभ लगातार बढ़ रहा है। पाँच वर्षों की अवधि (वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 तक) के दौरान, शुद्ध लाभ 1.66 लाख करोड़ रूपये से बढ़कर 2.91 लाख करोड़ रूपये हो गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा केंद्रीय खजाने में किए जा रहे लगातार बढ़ते और टिकाऊ योगदान को देखते हुए, सरकार की बिना सोचे–समझे अपनाई गई विनिवेश नीति पूरी तरह से आत्मघाती है। ये इकाईयां उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, केंद्र सरकार के कर्ज़ पर ब्याज, लाभांश और अन्य शुल्कों व करों के रूप में सरकार को भारी मात्रा में पूंजी का भुगतान करते रहे हैं। श्सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2024–25श के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में इनका कुल योगदान 24.03 लाख करोड़ रूपये रहा है। वित्त वर्ष 2024–25 में, इन इकाईयों ने केंद्रीय खजाने में 4.94 लाख करोड़ रुपयों का योगदान दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 2024–25 के लिए किए गए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सर्वे में सरकार ने खुद यह माना है कि, ष्केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में अपना योगदान देने में अहम भूमिका निभाते हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आने वाली गतिविधियों में शामिल हैं रू भूख और गरीबी मिटाना, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, शिक्षा और कौशल विकास, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए फंड में योगदान, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण की रक्षा, महिलाओं और अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण, खेल, कला और संस्कृति, सशस्त्र बलों का कल्याण आदि।

पिछले 5 सालों में, इन उपक्रमों ने सीएसआर में कुल मिलाकर 24,520 करोड़ रुपयों का योगदान दिया है।

आज जब भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है, तो यह कहना बेहद महत्वपूर्ण है कि ये सार्वजनिक उपक्रम बहुमूल्य विद. ेशी मुद्रा अर्जित करने में योगदान दे रहे हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान इन उपक्रमों ने कुल मिलाकर 6. 95 लाख करोड़ रुपयों की राशि अर्जित की है। अकेले वित्त वर्ष 2024–25 में ही, इन्होंने विदेशी मुद्राओं में 1.57 लाख करोड़ रूपये कमाए।

'सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध आत्मघाती नीतियों का पर्दाफ़ाश करो!'

सरकार द्वारा शुरू की गई 'नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति' , असल में नरेंद्र मोदी की उस कुख्यात घोषणा को लागू करने की कार्ययोजना है, जो उन्होंने चौंबर्स ऑफ़ कॉमर्स के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए की थी रू ष्सार्वजनिक क्षेत्र तो मरने के लिए ही पैदा हुआ है।ष ज़ाहिर है, ऐसी नीतियाँ व्यवस्थागत संकट से गहराई से जुड़ी हुई हैं, और यह पूँजीवाद के उस एकाधिकारवादी चरण का ही एक परिणाम हैं, जिस पर सत्ताधारी वर्ग के चहेते पूँजीपतियों का वर्चस्व है।

यह आक्रामक नव–उदारवादी सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट–खसोट की नीति को पूरी ज़ोर–शोर से, और वह भी बिना किसी रोक–टोक के, आगे बढ़ा रही है, जो उसकी वैचारिक और वर्गीय हताशा को दर्शाती है। सत्ता में काबिज़ दक्षिणपंथी पार्टी की विभाजनकारी चालों ने उन लोगों की चेतना को ही सुस्त कर दिया है, जिन्होंने इन संपत्तियों का निर्माण किया है और जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे ऐसी राष्ट्र–विरोधी नीतियों को हराने के लिए निर्णायक संघर्ष करेंगे। जिस तरह हमें अपने देश के प्रगतिशील इतिहास को याद रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक उसी तरह हमें आज़ादी के बाद भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका को भी याद रखना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा।

'(लेखक सीटू के राष्ट्रीय सचिव हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242–31650)'

जम्मू में जंगल और सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन शुरू

सबका जम्मू कश्मीर

विंटर कैपिटल के आसपास शिवा. लिक रेंज में जंगल और सरकारी ज़मीन पर बड़े पैमाने पर कब्ज़े के खिलाफ बुधवार को जम्मू में विरा. ध प्रदर्शन हुआ।

बहु विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विक्रम के नेतृत्व में रंधावा के नेतृत्व में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ष्जम्मू के जंगल बचाओष और ष्जम्मू की ज़मीन हड़पना बंद करोष लिखे प्लेकार्ड लेकर सिधरा रोड पर रैली निक. ाली और बाद में धरना दिया ।

प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और गैर–कानूनी कब्ज़े वालों को तुरंत हटाने की मांग की।

उन्होंने यह भी मांग की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नशा मुक्ति अभियान की तरह ष्अतिक्रमण मुक्त जम्मूष अभियान शुरू करें। मुक्त अभियान . प्रदर्शनकारियों ने कथित ष्बाहरी ज़मीन हड़पने वालोंष के खिलाफ़ नारे लगाए और चेतावनी दी कि अगर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।

इस वजह से सिधरा बाईपास दो घंटे से ज़्यादा समय तक ब्लॉक रहा।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, रंधावा ने कहा, ष्आज, हमने सरकार को गैर– डोगरा लोगों द्वारा इलाके की डेमोग्राफी बदलने की योजना के तहत किए जा रहे अतिक्रमण के बारे में बताने के लिए एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, जबकि अधिकारी कथित तौर पर इन जंगल वाले इलाकों में पानी , बिजली, सड़क और ड्रेनेज की सुविधाएं दे रहे हैं। ष

बठिंडी , सुंजवां , बजालता , सिधरा , राइका , नरवाल और बाहु जैसे इलाकों में जंगल की ज़मीन, सरकारी ज़मीन और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (श्रक।) की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया जा रहा है । ष्हजारों कनाल सरकारी और जंगल की ज़मीन पर जम्मू के बाहर से आए लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे दूसरे इलाकों में भी चुपचाप कब्ज़ा हो रहा है।ष

रंधावा ने दावा किया कि कश्मीर के लोग जम्मू में कब्ज़ा की हुई ज़मीन पर बस गए हैं, जबकि ष्जम्मू का कोई डोगरा कश्मीर में ज़मीन पर कब्ज़ा करके वहाँ नहीं बसा है।ष

, ष्मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहना चाहता हूं कि वे अतिक्रमण करने वालों की लिस्ट देखें और देखें कि वे कौन हैं। हम डोगरा संस्कृति, पहचान, विरासत और जम्मू के जंगलों को नष्ट नहीं होने देंगे। बीजेपी विधायक ने सरकार पर श्रक। और दूसरी सरकारी ज़मीनों पर कथित गैर–कानूनी कब्ज़े के बारे में बार–बार दी गई चेतावनियों को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ष्हम किसी के भी कानूनी तौर पर ज़मीन खरीदने और जम्मू में बसने का विरोध नहीं करते। लेकिन ज़मीन पर गैर–कानूनी कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि ज़िला प्रशासन, फ़ॉरेस्ट अथॉरिटी और श्रक। लैंड माफ़िया के खलिाफ़ कार्रवाई करें।ष

रंधावा ने मुख्यमंत्री और सत्ताधारी सरकार पर ष जम्मू की डोगरा पहचान को कमजोर करनेष का भी आरोप लगाया।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू ज़िले में 1,45,487 कनाल और छह मरला ज़मीन पर कब्ज़ा है, जबकि श्रीनगर में 13,862.95 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा है । इससे पता चलता है कि अकेले जम्मू ज़िले में श्रीनगर से 10 गुना ज़्यादा सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा है। अप्रैल में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा को बताया कि श्रक। की 16,000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया है और कहा कि इसे हटाने की कार्रवाई धीरे–धीरे की जा रही है।

नरिंदर सिंह रैना के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि श्रक। 80,976 कनाल और 10 मरला ज़मीन मैनेज करता है, जिसमें से 16,127 कनाल और 10 मरला पर गैर–कानूनी कब्ज़ा है।

जम्मू और कश्मीर में, एक कनाल 20 मरला के बराबर होता है और इसका माप लगभग 5,445 स्क्वायर फीट होता है, जबकि एक मरला लगभग 272 स्क्वायर फीट होता है।

किश्तवाड़ में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को मदद देने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू–कश्मीर पुलिस ने बुधवार को किश्तवाड़ जिले में आतंकी संगठन जैश –ए–मुहम्मद के सैफुल्लाह ग्रुप के विदेशी सदस्यों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और पनाह देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। अधिक. ारियों ने यह जानकारी दी।

गिरफ्तार किए गए लोगों में बेगपोरा निवासी मशकूर अहमद शामिल हैं। सिंहपोरा जो सरकारी स्कूल में टीचर थे, और मनीर अहमद, जो बंदेयान के रहने वाले थे नैदगाम .

ये गिरफ्तारियां इलाके में टेरर नेटवर्क को खत्म करने की अधिकारियों की लगातार कोशिशों के तहत हुईं।

22 फरवरी को सेना ने चटरू में जैश –ए–मुहम्मद के सैफुल्लाह ग्रुप के तीन आतंकवादियों को मार गिराया। यह आतंकी ग्रुप किश्तवाड़–डोडा बेल्ट के ऊपरी इलाकों में काम कर रहा था ।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ष्देश विरोधी तत्वों के खिलाफ एक अहम ऑपरेशन में, पुलिस ने किश्तवाड़ के सिंहपोरा–चतरू इलाके में एक ठिकाने से विदेशी आतंकवादियों को मदद देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मार्च में चटरू पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में एक ऑपरेशन के दौरान की गईं । भारतीय दंड संहिता की धाराओं 61 (2) (आपराधिक साजिश), 109 (हत्या का प्रयास), 147 (दंगा) और 148 (घातक हथियार से लैस होना) के तहत दर्ज किया गया था। न्याय संहिता और सेक्शन 13 (गैरकानूनी कामों के लिए सज़ा), 16 (आतंकवादी काम के लिए सज़ा), 18 (आतंकवादी काम की साज़िश, तैयारी), 19 (आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सज़ा) और 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होने के लिए सज़ा) गैरकानूनी काम (रोकथाम) एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत।

किश्तवाड़ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस नरेश कुमार ने कहा कि जांच के बाद मशकूर अहमद को गिरफ्तार किया गया , जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर के तौर पर काम करता था।

उन्होंने कहा कि आरोपी चटरू के सिंहपोरा इलाके में विदेशी आतंकवादियों के लिए एक ठिकाना बनाने में सीधे तौर पर शामिल था , जिससे वह इलाके में सक्रिय आतंकवादी गुर्गों को लॉजिस्टिक मदद दे रहा था।

उन्होंने कहा कि मनीर अहमद को पहले भी इसी तरह के अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने कहा कि जिले में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बड़े नेटवर्क का पता लगाने और उसे खत्म करने के लिए आगे की जांच चल रही है।

आतंकवाद और आतंकवाद के सपोर्टर्स के खिलाफ अपनी ष्ज़ीरो–टॉलरेंस पॉलिसीष दोहराते हुए, पुलिस ने देश विरोधी कामा. में मदद करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेता. वनी दी।

इस साल फरवरी में किश्तवाड़–उधमपुर में छह पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी मारे गए ।

जम्मू-कश्मीर में नशा विरोधी अभियान नशीले पदार्थों के खिलाफ क्रांति में बदल रहा है : एलजी

सबका जम्मू कश्मीर

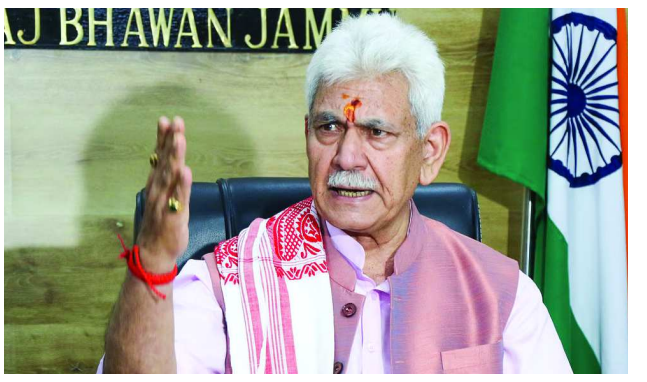

श्रीनगर : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सिन्हा ने बुधवार को कहा कि जम्मू–कश्मीर में एंटी–ड्रग कैंपेन ने ड्रग–स्मगलिंग इकोसिस्टम को गहरा झटका दिया है, और यह जन आंदोलन नारकोटिक्स के खिलाफ एक क्रांति में बदल रहा है।

इस अभियान का शीर्षक श नशा श है। श्मुक्त जम्मू–कश्मीर अभियान श बुधवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पहुंचा, जहां सिन्हा ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से मेन चौक तक पदयात्रा की। कुपवाड़ा । छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने पैदल मार्च में भाग लिया।

कहा, ष्आज कुपवाड़ा में , मैं श्ड्रग–फ्री जम्मू कश्मीर कैंपेनश के तहत पदयात्रा में शामिल हुआ और एक सभा को संबोधित किया। पिछले 32 दिनों में, हमने पूरे ड्रग स्मगलिंग इकोसिस्टम पर एक बड़ा झटका दिया है, और यह लोगों का आंदोलन नारकोटिक्स के खिलाफ एक क्रांति में बदल रहा है।ष

उन्होंने कहा कि प्रशासन की लगातार कार्रवाई से नार्को –टेररिस्ट नेटवर्क कमज़ोर हो रहे हैं।

करोड़ों की प्रॉपर्टी ज़ब्त की गई है, एसेट्स ज़ब्त किए गए हैं, और 15 स्मगलर्स के पासपोर्ट कैंसल करने की सिफारिश की गई है। 730 से ज़्यादा स्मगलर्स और पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है।ष

यह कैंपेन 11 अप्रैल को जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर के नेतृत्व में ड। स्टेडियम से एक बड़ी पदयात्रा (पैदल मार्च) के साथ शुरू हुआ। सिन्हा ने लाल किले में भी इसी तरह के मार्च का नेतृत्व किया। 3 मई को श्रीनगर शहर के चौक इलाके के साथ–साथ केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कर्फ्यू लगाया गया है।

बाद में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जब अप्रैल में कैंपेन शुरू किया गया था, तो कई लोगों को शक था कि ड्रग्स के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन मुमकिन है या नहीं और उन्होंने पक्के इरादे वाले गवर्नेंस के साथ जागरूक नागरिकों की ताकत को कम आंका था।

ष्पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लोगों की भागीदारी और भारी समर्थन से, जम्मू–कश्मीर के गांवों, शहरी मोहल्लों , स्कूलों, कॉलेजों और सड़कों पर सचमुच एक ऑर्गेनिक आंदोलन शुरू हो गया है।

जम्मू-कश्मीर में 93 प्रतिशत से ज़्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटल हुआ

सबका जम्मू कश्मीर

डिजिटलीकरण में 93.39 प्रतिशत प्रगति हासिल की है , और केंद्र शासित प्रदेश में 64 लाख से ज़्यादा ऐसे रिकॉर्ड को मंजूरी दी गई है, आधिकारिक डेटा में यह जानकारी दी गई है।

अधिकारियों ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का डिजिटाइज़ेशन, लैंड रिकॉर्ड्स के मॉडर्नाइज़ेशन प्रोग्राम के तहत सबसे बड़े सुधारों में से एक है, जिसका मकसद लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी पक्का करना है। ऑफिशियल डेटा के अनुसार, कुल 68,59,915 खसरों (रेवेन्यू रिकॉर्ड) में से 64,06,641 खसरों को अप्रूवल दिया जा चुका है , जबकि 3,04,549 मामले मेकर लेवल पर, 1,10,587 चेकर्स के पास और 38,138 अप्रूवर स्टेज पर पेंडिंग हैं।

सरकार ने 26 दिसंबर, 2025 को गलतियों को ठीक करने, बैकलॉग म्यूटेशन की एंट्री, पब्लिक वेरिफिकेशन और जमाबंदियों को फाइनल फ्रीज करने के लिए पूरी गाइडलाइन जारी की थीं । उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस को डिविजनल कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर (रेवेन्यू) की देखरेख में एक मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए रोज़ाना अपडेट किया जा रहा है।

डेटा के अनुसार, रामबन , शोपियां और गंदेरबल जिलों में सभी खसरा मंजूर होने के साथ 100 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और कोई पेंडेंसी नहीं है।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

केंद्रीय खान मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में 12 चूना पत्थर ब्लॉकों के लिए ई-नीलामी का दूसरा चरण शुरू किया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : केंद्रीय खान मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में 12 चूना पत्थर ब्लॉक के लिए ई-नीलामी का दूसरा चरण शुरू किया, जो केंद्र शासित प्रदेश में पारदर्शी, टिकाऊ और निवेशक-अनुकूल खनिज विकास की दिशा में एक और बड़ा मील का पत्थर है।

मिनिस्ट्री ऑफ़ माइंस के सेक्रेटरी पीयूष गोयल ने यहाँ एक फंक्शन में ऑफिशियली इस ट्रांच को लॉन्च किया। वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, उन्होंने मिनिस्ट्री द्वारा प्रोसेस को आसान बनाने, ट्रांसपेरेंसी को मज़बूत करने और माइनिंग सेक्टर में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए किए गए बड़े सुधारों और बदलावों के बारे में बताया।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि श्रज्ञ में मिनरल की बहुत ज़्यादा संभावना है और इन ब्लॉक्स की नीलामी और ऑपरेशनलाइज़ेशन से आर्थिक विकास, रोज़गार पैदा करने और इंडस्ट्रियल विकास के ज़रिए विकसित भारत, विकसित जम्मू और कश्मीर, और आत्मनिर्भर भारत के विज़न में अहम योगदान मिलेगा।

च्व्ठ ने एक हैंडआउट में कहा, ष्अनंतनाग, राजौरी और पुंछ ज़िलों में फैले कुल 12 लाइमस्टोन ब्लॉक्स को ट्रांच ￼ के तहत नीलामी के लिए रखा गया है। इनमें नए पहचाने गए ब्लॉक्स और मिनरल (ऑक्शन) रूल्स, 2015 (जैसा बदला गया है) के नियमों के मुताबिक, दूसरी कोशिश के तहत दोबारा नीलाम किए जा रहे ब्लॉक्स, दोनों शामिल हैं।ष

इसमें कहा गया है कि ये ब्लॉक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन (न्छथ्ब्) के ळ3 और ळ4 स्टेज में आते हैं और उम्मीद है कि इनमें इंडस्ट्री, खासकर सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अच्छी दिलचस्पी होगी।

इवेंट के दौरान, जॉइंट सेक्रेटरी और डेज़िग्नेटेड ऑफिसर, फरीदा एम नाइक ने बिडर्स से इस इलाके की माइनिंग क्षमता का पता लगाने की अपील की, और इकोनॉमिक ग्रोथ, रोज़गार और सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में इसकी भूमिका पर ज़ोर दिया।

टेंडर डॉक्यूमेंट्स की बिक्री 18 मई से शुरू होगी और प्री-बिड कॉन्फ्रेंस इस साल 5 जून को होगी।

यह नीलामी माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 और मिनरल (ऑक्शन) रूल्स, 2015 के नियमों के तहत की जाती है।

पहले हिस्से की रफ़्तार को आगे बढ़ाते हुए, यह पहल मिनरल रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल पक्का करने के लिए एक सोच-समझकर किया गया तरीका दिखाती है, साथ ही इन्वेस्टर की भागीदारी और भरोसा भी बढ़ाती है।

टेक्निकल सेशन में डम्ब्, ᐥठप्ब|चे और डैज्ब ने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिए।

डम्ब् के श्रीकांत शर्मा ने 12 लाइमस्टोन ब्लॉक्स की जियोलॉजिकल और मिनरल पोटेंशियल के बारे में बताया। च्व्ठ हैंडआउट के अनुसार, ᐥठप्ब|चे के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रतिन शर्मा ने मिनरल ऑक्शन प्रोसेस और टेंडर फ्रेमवर्क के बारे में बताया, जबकि डैज्ब के मैनेजर केशव अरोड़ा ने ई-ऑक्शन पोर्टल और ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस दिखाया।

उधमपुर प्रशासन ने नई आर्मी कैमोफ़्लाज यूनिफ़ॉर्म की बिना इजाज़त बिक्री पर रोक लगा दी है

सबका जम्मू कश्मीर

जम्म : प्रशासन ने मंगलवार को जिले में नई शुरू की गई इंडियन आर्मी की कैमोफ़्लाज यूनिफ़ॉर्म की बिना इजाज़त बिक्री पर पूरी तरह बैन लगाने का आदेश दिया, ताकि नकली वर्दी और गलत इस्तेमाल के मामलों को रोका जा सके।

यह आदेश यूनिफॉर्म के गलत इस्तेमाल की खबरों के बाद आया है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि एंटी-सोशल एलिमेंट्स इसका गलत इस्तेमाल सर्विसिंग स्टाफ की नकल करने के लिए कर सकते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि ऐसी घटनाएं एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय हैं और इन पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए।

बैन का ऑर्डर जारी करने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिंगा शेरपा ने कहा कि उधमपुर में मिलिट्री की अच्छी-खासी मौजूदगी है और यह नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर समेत कई डिफेंस जगहों के पास है, जिससे यह मामला खास तौर पर सेंसिटिव हो गया है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ष्प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें भारतीय सेना की नए पैटर्न वाली छलावरण वर्दी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।ष

उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद नकली सामान के मामलों को रोकना है और यह पक्का करना है कि ऑथराइज़्ड सामान और कपड़े का इस्तेमाल ऑथराइज़्ड सर्विस वाले ही करें, जिससे गलत इस्तेमाल का खतरा खत्म हो जाए।

अधिकारी ने कहा, ष्यहां सेना से जुड़ी कई दुकानें हैं क्योंकि इस इलाके में बड़ी संख्या में सेना के जवान मौजूद हैं। इसलिए यह रोक लगाई गई है।

प्रशासन ने निर्देश दिया है कि जिले में कोई भी बिना इजाज़त वाली दुकान नए डिज़ाइन वाले कैमोफ़्लाज फ़ैब्रिक या आर्म्ड फ़ोर्स के जवानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली यूनिफ़ॉर्म नहीं बेचेगी। एनफ़ोर्समेंट टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और नियम तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें।

डीसी ने कहा, ष्उधमपुर के संबंधित ᐥभ्ͼ को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि कोई भी दुकान ऐसा कपड़ा न बेचे, जिसका इस्तेमाल लोग उधमपुर में आर्मी के जवानों का दिखावा करने के लिए कर सकें।ष

अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि वे सावधान रहें और आर्मी पैटर्न वाले कपड़ों की गैर-कानूनी बिक्री या गलत इस्तेमाल की किसी भी घटना की तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को रिपोर्ट करें।

उपराज्यपाल ने परिवार और समुदाय के सपोर्ट से जुड़े एक्शन के लिए दो एंटी-ड्रग प्रोग्राम शुरू किए

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को न्ज में चल रहे एंटी-ड्रग कैंपेन के तहत दो पहल शुरू कीं और कहा कि नशे के शिकार लोगों के साथ इज्ज़त से पेश आना चाहिए, और उन्हें हिम्मत और दया के ज़रिए समाज की मेनस्ट्रीम से फिर से जोड़ना चाहिए।

यह बात तब आई जब सिन्हा ने 5 अप्रैल को शुरू हुए 100 दिन के श्नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियानश के तहत बारामूला में एक मार्च का नेतृत्व किया और नागरिकों से बातचीत की।

स्ळ ने दो नई पहल —— कम्युनिटी इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम और फ़ैमिली फ़ोर्ट्रेस इनिशिएटिव —— शुरू कीं, और उन्होंने कहा कि ये अगले 69 दिनों तक कैंपेन के तहत दो नए पिलर के तौर पर काम करेंगी।

सिन्हा ने कहा कि जैसे कम्युनिटी को बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन करना सिखाया गया है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन हर जिले में पांच से 10 हाई-रिस्क हॉटस्पॉट एरिया में ड्रग्स के खिलाफ कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन पक्का करने के लिए धार्मिक नेताओं और सोशल ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप करेगा।

उन्होंने कहा, ष्मैं स्कूलों, मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों और छळव्े से अपील करता हूं कि वे जागरूकता के ज़रिए इस पहल को मज़बूत करने के लिए हर हफ़्ते एक घंटा दें। इससे असली नतीजे मिलेंगे, यह हॉटस्पॉट पर नज़र रखने वाले अर्ली वॉर्निंग सिस्टम की तरह काम करेगा और उन्हें पूरी तरह से ड्रग-फ़्री ज़ोन बनाएगा।ष

स्ळ ने कहा कि फैमिली फोर्ट्रेस इनिशिएटिव ड्रग्स की लत के खिलाफ आखिरी सुरक्षा के लिए परिवार और समुदाय के मजबूत रिश्तों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, अगले 69 दिनों में, जम्मू-कश्मीर के हर स्कूल, कॉलेज और पूजा की जगह पर ड्रग्स पर हर हफ़्ते फ़ैमिली डायलॉग होना चाहिए। ये डायलॉग खुले और ईमानदार होने चाहिए, और कमियों को पहचानने और ठीक करने के लिए लोकल कैंपेन ऑडिट के साथ होने चाहिए।

सिन्हा ने बताया कि पिछले 31 दिनों में, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 2,35,000 से ज़्यादा जागरूकता और आउटरीच इवेंट हुए हैं। उन्होंने कहा कि 44,000 से ज़्यादा व्व्क मरीज़ों का इलाज किया गया है, लगभग 700 ड्रग तस्करों और पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है और ड्रग सप्लाई चेन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। ष्कार्रवाई में ड्रग कार्टेल के हर फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को टारगेट किया गया है, बड़े तस्करों द्वारा ड्रग के पैसे से बनाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी ज़ब्त की गई हैं। जम्मू और कश्मीर डिवीज़न में, ड्रग तस्करों से जुड़े 300 ड्राइविंग लाइसेंस और 400 से ज़्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कैंसल करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा, ष्एनफोर्समेंट एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खेप पकड़ी है। हमने 3,300 से ज़्यादा दवा की दुकानों की जांच की है, और नियमों का उल्लंघन करने पर 150 लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। सिन्हा ने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में दवा की दुकानों पर अब लगभग 3,000 ब्ब्ज्ट कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, पीआईटीएनडीपीएस एक्ट के तहत दो दर्जन से ज़्यादा तस्करों को पकड़ा गया है। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम ड्रग तस्करों के हर रुपये, हर संपत्ति और शेल कंपनी का पीछा करेंगे, और हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे।

जम्मू में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने मंगलवार को जिले की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और अपराध नियंत्रण को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिले के विभिन्न पुलिस अधिकारियों, विशेष शाखा के अधिकारियों तथा क्षेत्रीय इकाइयों से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा सुरक्षा स्थिति का आकलन करना, खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को और मजबूत बनाना तथा समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की समीक्षा करना था।

बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू पुलिस समाज विरोधी तत्वों, नशा तस्करों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ "शून्य सहनशीलता" की नीति पर काम कर रही है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए पुलिस को जमीनी स्तर पर अपनी मौजूदगी लगातार मजबूत करनी होगी।

उन्होंने मानव खुफिया तंत्र के महत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रभावी पुलिसिंग केवल आधुनिक तकनीक के सहारे संभव नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर मजबूत संपर्क और विश्वसनीय सूचना तंत्र भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ बेहतर तालमेल और स्थानीय सूत्रों से समय पर प्राप्त जानकारी पुलिस को अपराध तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तकनीक आज के समय में एक आवश्यक साधन बन चुकी है, लेकिन वास्तविक समय में मिलने वाली जमीनी सूचनाएं अभी भी सबसे अधिक प्रभावी साबित होती हैं।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाएं और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराध को पहले ही रोकना होना चाहिए। इसके लिए हर स्तर पर समन्वय और सतर्कता जरूरी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और क्षेत्रीय पुलिस कर्मियों से कहा कि वे जनता के साथ संवाद बनाए रखें और लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों का सहयोग पुलिस के लिए सबसे बड़ी ताकत है और जनता के सहयोग के बिना किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकती। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें और किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें।

बैठक के दौरान जिले में चल रहे नशा विरोधी अभियान की भी विस्तार से समीक्षा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने जिला विशेष शाखा की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर हाल के समय में कई नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है, जिससे बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर
संपादकीय

सशक्त भारत यात्रा

संपादक – राज कुमार

16 मई 2014 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया। इस दिन देश की जनता ने ऐसा जनादेश दिया जिसने भारत की राजनीति, शासन व्यवस्था और विकास की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले बारह वर्षों में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखे हैं। यह केवल योजनाओं और घोषणाओं की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेतृत्व की यात्रा है जिसने देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को नई ऊर्जा दी और भारत को वैश्विक मंच पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। मोदी सरकार की विकास यात्रा की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से हुई। वर्ष 2014 में शुरू किए गए इस अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन बना दिया। करोड़ों शौचालयों के निर्माण ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी और महिलाओं को सम्मान तथा सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद डिजिटल इंडिया अभियान ने तकनीक को आम नागरिक तक पहुंचाकर शासन को अधिक पारदर्शी और तेज बनाया। आधार, यूपीआई और डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारत को डिजिटल क्रांति के केंद्र में ला खड़ा किया। आज भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन करने वाला देश बन चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने कठोर और निर्णायक नीति अपनाई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इस नीति ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया और देश की सामरिक क्षमता को नई पहचान दी। आर्थिक सुधारों में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। इसने पूरे देश को एकीकृत बाजार में बदल दिया और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया। आगे चलकर जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के माध्यम से टैक्स व्यवस्था को और सरल तथा जनहितक. ारी बनाया गया। इससे व्यापार जगत को राहत मिली और आम नागरिकों पर कर का बोझ कम हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निरंतर विकास दर बनाए रखी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान कायम रखी। गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। मुफ्त गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य बीमा, आवास और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता ने ग्रामीण और गरीब परिवारों को नई उम्मीद दी। इन योजनाओं के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की यह सोच स्पष्ट दिखाई देती है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय भारत की एकता और अखंडता की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना गया। जम्मू–कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ ही वहां विकास और शांति का नया दौर शुरू हुआ। इसी अवधि में जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पेयजल पहुंचाने का अभियान भी तेजी से आगे बढ़ा। कोविड–19 महामारी के दौरान मोदी सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। देशव्यापी लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने भारत को इस संकट से उबरने में मदद की। कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना भारत की प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण बना। इसी समय आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई योजनाओं ने घरेलू उत्पादन और विनिर्माण को नई गति दी। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की नीति ने भी उल्लेखनीय परिणाम दिए। सुरक्षा अभियान, सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसी विकास योजनाओं के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता और शांति स्थापित हुई। मार्च 2026 में भारत को नक्सल मुक्त घोषित किया जाना इसी प्रयास का परिणाम माना गया। सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी मोदी युग की महत्वपूर्ण पहचान बनकर उभरा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय था, जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में हुआ। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत गौरव का प्रतीक बन गया। आज भारत वैश्विक राजनी. ति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक मामलों में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभर चुका है। पिछले बारह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने देश को आत्मविश्वास, विकास और नई पहचान दी है। यह यात्रा केवल उपलब्धियों की सूची नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत की कहानी है जो आत्मनिर्भर, सशक्त और विश्व मंच पर नेतृत्व करने के लिए तैयार दिखाई देता है।

चीन के मुकाबले भारत की रक्षा तैयारी कितनी मजबूत है? संसाधन और ताकत के मामले में कौन-सा देश आगे है?

सबसे पहले सैन्य संख्या की बात करें तो चीन के पास लगभग बीस लाख सक्रिय सैनिक हैं जबकि भारत के पास करीब चौदह से पंद्रह लाख के बीच सक्रिय सेना है। पहली नजर में यह अंतर बड़ा लगता है, लेकिन युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता।

नीरज कुमार दुबे

एशिया की भू राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। एक तरफ विस्तारवादी मंशा से आगे बढ़ता चीन है और दूसरी तरफ तेजी से आत्मनिर्भर और आक्रामक रणनीति अपनाता भारत है। सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बल्कि सवाल यह है कि अगर टकराव हुआ तो कौन भारी पड़ेगा। तथ्य बताते हैं कि चीन अभी भी संसाधनों और संख्या के मामले में आगे है, लेकिन भारत ने पिछले एक दशक में जो रणनीतिक बदलाव किए हैं, उन्होंने इस अंतर को तेजी से कम किया है।

यह वीनर्स नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है! और कीमत बहुत सस्ती है

सबसे पहले सैन्य संख्या की बात करें तो चीन के पास लगभग बीस लाख सक्रिय सैनिक हैं जबकि भारत के पास करीब चौदह से पंद्रह लाख के बीच सक्रिय सेना है। पहली नजर में यह अंतर बड़ा लगता है, लेकिन युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता। भारत के पास अर्धसैनिक बलों का विशाल ढांचा है जो युद्ध की स्थिति में बड़ी ताकत बन सकता है।

हथियारों और तकनीक की बात करें तो वायु शक्ति के मामले में तस्वीर साफ तौर पर चीन के पक्ष में झुकी हुई नजर आती है। कुल सैन्य विमान बेड़े में चीन के पास लगभग 3300 से अधिक विमान हैं, जबकि भारत के पास करीब 2229 विमान हैं। यानी संख्या के लिहाज से चीन को स्पष्ट बढ़त हासिल है। अगर केवल लड़ाकू विमानों की बात करें तो यह अंतर और भी चौड़ा हो जाता है। चीन के पास करीब 2000 से 2100 लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारत के पास लगभग 550 से 600 के बीच फाइटर जेट हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि सीधे हवाई टकराव की स्थिति में चीन की संख्या आधारित ताकत भारी पड़ सकती है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। भारत की वायुसेना केवल संख्या पर नहीं, बल्कि संतुलित संरचना, मल्टी रोल क्षमता और रणनीतिक तैनाती पर आधारित है, जो उसे हर हालात में जवाब देने लायक बनाती है।

इसके अलावा यह भी तथ्य अहम है कि भारत इस अंतर को तेजी से कम करने की दिशा में आक्रामक कदम उठा चुका है। भारत ने फ्रांस के साथ बड़े स्तर पर रक्षा करार करते हुए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है, जो विमानवाहक पोतों पर तैनात होंगे और समुद्री युद्ध क्षमता को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही भारत 114 नए मल्टी रोल राफेल लड़ाकू विमानों के बड़े सौदे की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, जो वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इतना ही नहीं, फ्रांस के साथ संयुक्त उत्पादन, हेलिकॉप्टर निर्माण और मिसाइल सिस्टम के सह उत्पादन जैसे समझौते भी किए जा रहे हैं, जिससे भारत न केवल अपनी वायु शक्ति बढ़ा रहा है बल्कि आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वायु शक्ति बढ़ाने के लिए भारत कई अन्य देशों से भी खरीद के मुद्दे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का युद्ध अनुभव चीन से कहीं अधिक व्यावहारिक है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध की बात करें तो भारतीय सेना का अनुभव लद्दाख और सियाचिन जैसे क्षेत्रों में चीन से कहीं आगे है। यह वह मोर्चा है जहां आंकड़े नहीं बल्कि जमीनी हकीकत जीत तय करती है।

इसके अलावा, जमीनी युद्ध की स्थिति में हिमालय भारत के लिए एक प्राकृतिक किला बन जाता है। चीन की भारी सेना और उपकरण इस इलाके में उतने प्रभावी नहीं रह जाते जितने खुले मैदान में होते हैं। भारतीय सेना ने दशकों तक इन परिस्थितियों में खुद को ढाला है, जबकि चीन को इस तरह की चुनौतियों का सीमित अनुभव है।

वहीं तोपखाने और तैनाती की बात करें तो भारत की स्थिति कई मामलों में मजबूत है। ऊंचाई पर तेजी से हथियार पहुंचाने और उन्हें संचालित करने की क्षमता भारत की बड़ी ताकत है।

नौसेना के क्षेत्र में तस्वीर थोड़ी अलग है। चीन की नौसेना आकार में बड़ी है, लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक बढ़त देती है। हिंद महासागर में भारत का प्रभाव चीन के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। भारत के पास विमानवाहक पोत हैं और समुद्री मार्गों पर उसकी पकड़ मजबूत है। युद्ध की स्थिति में यह क्षेत्र चीन की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है।

अब बात आती है आधुनिक युद्ध की, जहां असली खेल साइबर और अंतरिक्ष में हो रहा है। इस क्षेत्र में चीन ने तेजी से बढ़त बनाई है। साइबर हमले, उपग्रह तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में चीन आगे है। भारत ने इस दिशा में कदम जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन अभी काफी दूरी तय करनी बाकी है। यही वह क्षेत्र है जो आने वाले समय में युद्ध की दिशा तय करेगा।

देखा जाये तो सामरिक दृष्टि से यह मुकाबला केवल दो देशों के बीच नहीं है। यह पूरे एशिया में शक्ति संतुलन की लड़ाई है। भारत अब केवल सीमा की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाएं और वैश्विक साझेदारियां इस दिशा में साफ संकेत देती हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र प्रथम नीति ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। इस नीति का सीधा असर रक्षा क्षेत्र में दिख रहा है। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद उत्पादन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीमा क्षेत्रों में सड़कों और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास, सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करना और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना इस नीति के प्रमुख स्तंभ हैं। इसका परिणाम यह है कि भारत अब जवाबी रणनीति अपनाने की स्थिति में आ चुका है। बहरहाल, यह एक तथ्य है कि चीन अभी भी संसाधनों, बजट और तकनीक में आगे है। लेकिन भारत ने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना शुरू कर दिया है। भूगोल, अनुभव और रणनीतिक सोच भारत को इस मुकाबले में मजबूती देते हैं। अगर टकराव होता है तो यह एकतरफा नहीं होगा। भारत अब वह देश नहीं है जो दबाव में झुक जाए। यह एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो चुनौती को स्वीकार करता है और जवाब देने की क्षमता रखता है। डोकलाम और गलवान दिखा चुके हैं कि भारत अब चीन के मुक. ाबले में पीछे नहीं, बल्कि बराबरी पर खड़ा है।

–नीरज कुमार दुबे

(इस लेख में लेखक के अपने विचार

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू में छात्रों को साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

सबका जम्मू कश्मीर

जम्म : साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस (सीआईसीई) जम्मू द्वारा साथ मिलकर सुरक्षित डिजिटल भारत का निर्माण मिशन के तहत गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रेलवे कॉलोनी जम्मू में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन डीएसपी अलबीना मलिक एसएचओ सीआईसीई जम्मू द्वारा किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग ऑनलाइन ठगी साइबर बुलिंग सुरक्षित इंटरनेट उपयोग तथा डिजिटल खतरों से बचाव के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय मजबूत पासवर्ड के महत्व साइबर घटनाओं की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 एवं एनसीआरपी पोर्टल के उपयोग तथा जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

इस दौरान विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी निभाई। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती निशात अख्तर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की साइबर सुरक्षा से जुड़ी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया। अधिकारियों ने लोगा. ं से अपील करते हुए कहा कि किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में बिना डर के तुरंत शिकायत दर्ज कराएं तथा सतर्क और सुरक्षित रहें।

पीओजेके विस्थापित सेवा समिति की बैठक आयोजित एसटी दर्जे की मांग दोहराई

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : पीओजेके विस्थापित सेवा समिति की प्रांत टीम की एक महत्वपूर्ण बैठक वेद मंदिर कॉम्प्लेक्स अम्फल्ला स्थित समिति कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा हाल के समय में किए गए कार्यों की समीक्षा एवं मूल्यांकन किया गया।

समिति के अध्यक्ष डॉ. दीपक कपूर ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि पीओजेके विस्थापितों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने संबंधी मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि पुंछ राजौरी और कुपवाड़ा सहित विभिन्न जिलों में रह रहे पीओजेके विस्थापितों को एसटी दर्जा प्रदान किए जाने के मुद्दे पर फॉलोअप प्रक्रिया को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार को एक पत्र भेजकर जम्मू–कश्मीर से बाहर बसे पीओजेके विस्थापितों के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की समय–सीमा बढ़ाने की मांग की गई है।

समिति के महासचिव अरुण चौधरी ने कहा कि वर्ष 1947 से विस्थापन का दंश झेल रहे पीओजेके विस्थापितों को जल्द से जल्द एसटी दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए।

बैठक में अमरीक सिंह प्रीति चौधरी वीणा खन्ना देविंदर शुभम नरेश वोहरा आर.सी. गुप्ता जगदेव सिंह अशोक खजूरिया सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

ईंधन संरक्षण को लेकर विधायक अरविंद गुप्ता ने पेश की नई मिसाल

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों और ईंधन की बढ़ती मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल और डीजल के सीमित उपयोग की अपील के बाद जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक नई पहल करते हुए सरकारी वाहन के बजाय अपनी निजी विद्युत वाहन का उपयोग शुरू किया है। उनके इस कदम को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और जिम्मेदार सार्वजनिक जीवन की दिशा में एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

जनसंपर्क और क्षेत्रीय गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले विधायक अरविंद गुप्ता अब जम्मू शहर में अपने अधिकांश आधिकारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में विद्युत वाहन से पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस पहल को केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी से जुड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि जब देश ऊर्जा संरक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें। मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऊर्जा संरक्षण, सतत विकास और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल एक सामान्य संदेश नहीं बल्कि राष्ट्रहित से जुड़ा विषय है। ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका समझनी होगी और ईंधन की अनावश्यक खपत को कम करने के लिए प्रयास करने होंगे।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को केवल भाषण देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने व्यवहार और कार्यों से भी समाज को प्रेरित करना चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने सरकारी वाहन का कम उपयोग करने और विद्युत वाहन अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यदि समाज में अधिक लोग धीरे–धीरे स्वच्छ परिवहन के साधनों की ओर बढ़ेंगे तो इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। अरविंद गुप्ता ने कहा कि आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ऊर्जा संकट जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता बन चुका है।

उन्होंने कहा कि विद्युत वाहन न केवल प्रदूषण कम करते हैं बल्कि पेट्रोल और डीजल पर होने वाले खर्च को भी कम करते हैं। इसके साथ ही आयातित ईंधन पर निर्भरता घटने से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।

उन्होंने "आत्मनिर्भर भारत" के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता देश की आर्थिक और रणनीतिक मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यदि देश ईंधन आयात पर कम निर्भर होगा तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी और राष्ट्रीय संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि छोटे–छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बड़े राष्ट्रीय परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।

विधायक ने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाएं। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग, विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने और ईंधन की बर्बादी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देना हम सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए समाज को मिलकर कार्य करना होगा।

अरविंद गुप्ता की इस पहल को स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कई नागरिकों ने इसे प्रतीकात्मक राजनीति से आगे बढ़कर व्यवहारिक नेतृत्व का उदाहरण बताया। लोगा. ं का कहना है कि जब जनप्रतिनिधि स्वयं पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत की दिशा में कदम उठाते हैं तो उसका व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ता है और आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज देश में प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है।

ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना एक प्रेरणादायक पहल है। उनका मानना है कि यदि अन्य नेता और अधिकारी भी इसी प्रकार के कदम उठाएं तो समाज में ऊर्जा संरक्षण को लेकर सकारात्मक माहौल तैयार हो सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि विद्युत वाहनों का बढ़ता उपयोग भविष्य की आवश्यकता है। सरकार पहले ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को प्रोत्साहित कर रही है।

रेखा महाजन और अरूण शर्मा ने सुनीं लोगों की समस्याएं

सबका जम्मू कश्मीर

जम्म : भारतीय जनता पार्टी की जम्मू–कश्मीर इकाई की उपाध्यक्ष रेखा महाजन और प्रदेश सचिव अरुण शर्मा ने सोमवार को जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनीं और उन्हें शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पार्टी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपने क्षेत्र तथा व्यक्तिगत समस्याओं को नेताओं के समक्ष रखा।

जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, पेंशन, नागरिक सुविधाओं, विकास कार्यों, सार्वजनिक सेवाओं तथा अन्य प्रशास. निक मामलों से जुड़ी समस्याएं उठाईं। कई प्रतिनिधिमंडलों ने अपने–अपने क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, विकास कार्यों में देरी और सरकारी योजनाओं के लाभ समय पर नहीं मिलने से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज कराईं।

लोगों ने आशा व्यक्त की कि पार्टी नेतृत्व के हस्तक्षेप से उनकी समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा।

कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी समस्याओं को गंभीरता से संबंधित विभागों और अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। कई लोगों ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं से सीधे संवाद का अवसर मिलने से आम जनता की समस्याएं प्रभावी ढंग से सामने आ पाती हैं और समाधान की प्रक्रिया तेज होती है।

इस अवसर पर लोगों से बातचीत करते हुए रेखा महाजन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यशैली हमेशा जनसंपर्क और जनभागीदारी पर आधारित रही है। जनता की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए प्रयास करना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मानना है कि जनता से सीधा संपर्क बनाए रखने से वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है और समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है।

रेखा महाजन ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं और प्रशासन तथा आम लोगों के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहें और किसी भी वास्तविक समस्या को अनसुना न होने दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनसुनवाई के दौरान उठाए गए सभी मामलों को संबंधित विभागों और अधिकारियों के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा ताकि लोगों को शीघ्र राहत मिल सके।

नीट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन, उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू–कश्मीर कांग्रेस ने बुधवार को छम्म्ज्–न्ळ परीक्षा रद्द करने को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कथित पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की मांग की। भल्ला के नेतृत्व में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र का पुतला फूंका प्रधान ने छम्म्ज परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। भल्ला ने रिपोर्टर्स से कहा, "हम कथित हाई–लेवल नेक्सस को सामने लाने और एग्जामिनेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स का भरोसा वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। हम भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पक्का करने के लिए एक फुलप्रूफ सिस्टम चाहते हैं।"

ये विरोध तब हुआ जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (छज।) ने 3 मई को हुई छम्म्ज (न्ळ) 2026 को कैंसिल करने का ऐलान किया। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा दोबारा होगी और तारीखें अलग से बताई जाएंगी। एजेंसी ने यह भी कहा कि ब्ठप् परीक्षा से जुड़े आरोपों की पूरी जांच करेगी।

कथित छम्म्ज पेपर लीक विवाद और जम्मू–कश्मीर में भर्ती घोटालों की एक सीरीज़ को लेकर ठश्रच के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, भल्ला ने सरकार पर "युवाआ. ॅ के भविष्य के साथ खेलने" का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब से ठश्रच केंद्र में सत्ता में आई है, पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई हैं और उन्होंने बिहार और राजस्थान में छम्म्ज परीक्षाओं से जुड़ी कथित गड़बड़ियों का भी ज़िक्र किया। भल्ला ने कहा कि छम्म्ज परीक्षा पैटर्न को लेकर बार–बार होने वाले विवादों ने देश के शिक्षा सिस्टम को शर्मसार किया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों से जवाबदेही की मांग की।

उन्होंने कहा, ष्पेपर लीक मामलों में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को इस्तीफा देना चाहिए।ष्

स्टूडेंट्स की महीनों की तैयारी के बाद एग्जाम पोस्टपोन करने पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि ऐसे फैसलों से स्टूडेंट्स के हौसले और फोकस पर बुरा असर पड़ता है।

भल्ला ने कहा, "स्टूडेंट्स लगन और मेहनत से तैयारी करते हैं। पेपर लीक होने के बाद एग्जाम पोस्टपोन होने से उनके फोकस और मेंटल तैयारी पर बुरा असर पड़ता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।"

ठश्रच पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी और डेवलपमेंट का वादा किया था, लेकिन एग्जाम स्कैम और पेपर लीक को रोकने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी घटनाओं की वजह से अनिश्चितता का सामना कर रहे स्टूडेंट्स और युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है।

भल्ला ने 2014 के बाद जम्मू–कश्मीर में रिपोर्ट किए गए रिक्रूटमेंट स्कैम का भी ज़िक्र किया, जिसमें फायर सर्विस, अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर इंजी. नियर और सब–इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में कथित गड़बड़ियां शामिल हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई रिक्रूटमेंट स्कैम मामलों में असरदार लिंक सामने आए हैं और केंद्र से अपील की कि वह "चुप रहने" के बजाय करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन ले।

कठुआ में सफल एंटी–टेरर ऑपरेशन के लिए 70 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : कठुआ जिले में इस साल की शुरुआत में चलाए गए 17 दिन लंबे सफल एंटी–टेरर ऑपरेशन में अपनी भूमिका के लिए 70 कर्मियों को सम्मानित किया। मंगलवार को कठुआ की जिला पुलिस लाइन में यह कमेंडेशन सेरेमनी ऑर्गनाइज़ की गई थी। इसमें ऑपरेशन से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया । यह ऑपरेशन इस साल 7 जनवरी से 23 जनवरी तक कठुआ जिले के बिलावर पहाड़ी इलाके के पडेतर इलाके में चला था। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान, सुरक्षा बलों ने पडेतर के मुश्किल इलाके में एक बड़े घेरे और तलाशी अभियान के बाद जैश –ए–मोहम्मद के एक आतंकवादी को मार गिराया , जिसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। कठुआ पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप के 70 जवानों को खुफिया जानक. ारी इकट्ठा करने, इलाके पर कब्ज़ा करने और ऑपरेशन को पूरा करने में उनके योगदान के लिए कैश इनाम और तारीफ़ सर्टिफ़िकेट से सम्मानित किया गया। कठुआ की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस, मोहिता शर्मा ने फंक्शन की अध्यक्षता की और ऑपरेशन के दौरान पुलिसवालों की हिम्मत, प्रोफेशनलिज़्म और डेडिकेशन की तारीफ़ की। लोगों को संबोधित करते हुए ैच ने कहा कि यह सफल ऑपरेशन कठुआ पुलिस के शांति बनाए रखने और आतंकी संगठनों के इरादों को नाकाम करने के पक्के इरादे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑपरेशन बिना रुकावट के तालमेल, समय पर खुफिया जानकारी और ज़मीन पर मौजूद सेना की बहादुरी की वजह से सफल होते हैं।

कठुआ गांव में भटका तेंदुआ , तनावपूर्ण ऑपरेशन के बाद बचाया गया

सबका जम्मू कश्मीर

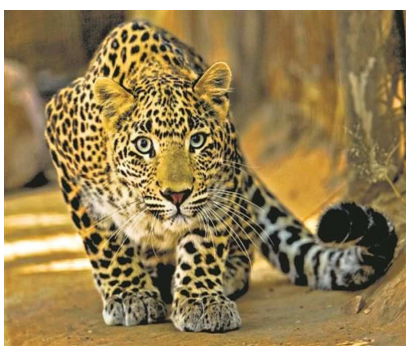

जम्मू : जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में वाइल्डलाइफ अधिकारियों ने मंगलवार को एक तेंदुए को बचाया जो एक गांव में भटक गया था और एक ग्रामीण के शेड में शरण ले ली थी। तेंदुए ने पाका में एक इमारत के अंदर शरण ली थी दयाल का कोठा इलाका चक गांव में आग लगने से वहां के लोगों में डर फैल गया है।

बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे एक वन्यजीव अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया, ष्जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारी टीम ने तुरंत सभी उपलब्ध कर्मचारियों को इकट्ठा किया और मौके पर पहुंच गई।ष्

अधिकारियों के अनुसार, तेंदुआ घायल लग रहा था और अस्त–व्यस्त स्टोर रूम में फंस गया था, जो जलाने की लकड़ी और घर के दूसरे सामानों से भरा हुआ था।

अधिकारी ने कहा, ष्जब हम जांच के लिए कमरे में दाखिल हुए तो हमने देखा कि तेंदुआ चीजों के नीचे छिपा हुआ था।ष्

तंग और अस्त–व्यस्त जगह की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो गया, और अधिक. ारियों को शुरू में जानवर को ट्रैंक्विलाइज़ करने में मुश्किल हुई।

उन्होंने कहा, "तेंदुआ साफ़ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए दो डार्ट बेकार हो गए। ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ी।"

आखिरकार रेस्क्यू टीम ने टिन शेड की छत से तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज़ करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

अधिकारी ने कहा, ष्हमने टिन की छत के ज़रिए ऊपर से उसे शांत किया और बाद में उसे सुरक्षित बचा लिया। जानवर को अब मांडा जू में शिफ़्ट किया जाएगा।ष्

द्रविन्दर सिंह, नंबरदार जिनका स्टोर रूम तेंदुए के छिपने की जगह बन गया था, ने कहा कि गांव वालों को राहत मिली कि कोई घायल नहीं हुआ।

नीट स्नातक परीक्षा रद्द, पेपर लीक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंगलवार को तीन मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2026 को रद्द करने की घोषणा कर दी। यह फैसला प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच लिया गया है। केंद्र सरकार ने पूरे मामले की विस्तृत जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय लिया है। अब यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और इसकी नई तिथियों की घोषणा अलग से की जाएगी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सामाजिक माध्यम मंच पर जारी बयान में कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और छात्रों का विश्वास कायम रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं और जांच रिपोर्टों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को उसी रूप में जारी रखना उचित नहीं होगा।

एजेंसी के अनुसार सरकार की मंजूरी के बाद तीन मई को आयोजित परीक्षा को रद्द करने तथा दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। एजेंसी ने यह भी कहा कि दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा की तिथियां, प्रवेश पत्र जारी करने का कार्यक्रम और अन्य जानकारियां आगामी दिनों में आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएंगी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच के लिए सरकार ने इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि वह जांच एजेंसी को हर संभव सहयोग देगी और जांच से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेख, सामग्री तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बयान में कहा गया कि यह निर्णय छात्रों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि एजेंसी ने स्वीकार किया कि परीक्षा दोबारा आयोजित होने से लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन परीक्षा प्रणाली में जनता के भरोसे को बनाए रखना इससे भी अधिक आवश्यक है।

एजेंसी का कहना है कि यदि परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप सामने आते हैं और उन पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती, तो इससे पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

एजेंसी के अनुसार मई 2026 सत्र के लिए किए गए पंजीकरण, परीक्षा केंद्रों और अन्य अभिलेखों का उपयोग दोबारा होने वाली परीक्षा में किया जाएगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता अभियान

कठुआ में डेंगू से बचाव को लेकर लोगों को किया गया जागरूक

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर चीफ मेडिकल ऑफिसर कार्यालय कठुआ और जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी देना था।

चीफ मेडिकल ऑफिसर कार्यालय कठुआ में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उत्तम चंद ने जागरूकता व्याख्यान दिया। इस दौरान चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. विजय रैना, मलेरिया विभाग का स्टाफ और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों को बताया गया कि डेंगू से बचाव के लिए साफ–सफाई रखना और पानी जमा न होने देना जरूरी है। साथ ही बुखार होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लेने की अपील की गई। अधिकारियों ने विशेष रूप से एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसी दवाओं से बचने की सलाह दी। इस मौके पर डेंगू जागरूकता वैन को भी रवाना किया गया, जो लोगों को बारिश के मौसम में डेंगू से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जीएमसी कठुआ में डेंगू जांच, प्लेटलेट सुविधा और मरीजों के लिए अलग बेड की व्यवस्था की गई है। जिले के परोल, हीरानगर, बिलावर, बसोहली और बनी क्षेत्रों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया स्टाफ और ब्लॉक मेडिकल अधिकारियों को डेंगू मामलों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पैडेटर आतंकी ऑपरेशन में बहादुरी दिखाने वाले 70 पुलिसकर्मी सम्मानित

कठुआ पुलिस ने नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर बढ़ाया जवानों का हौसला

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, जम्मू–कश्मीर पुलिस कठुआ ने पैडेटर, बिलावर में सफल आतंकी विरोधी अभियान में शामिल 70 पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। जिला पुलिस लाइन कठुआ में आयोजित समारोह में इन सभी को नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र दिए गए।

यह ऑपरेशन 7 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 तक चला। अभियान के दौरान जैश–ए–मोहम्मद के आतंकी उस्मान को मार गिराया गया। कठिन पहाड़ी इलाके में चले इस लंबे ऑपरेशन को कठुआ पुलिस और जम्मू–कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने मिलकर अंजाम दिया।

समारोह की अध्यक्षता एसएसपी कठुआ मोहित शर्मा (आईपीएस) ने की। इस मौके पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।

एसएसपी मोहित शर्मा ने जवानों की बहादुरी, मेहनत और टीमवर्क की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती से काम कर रही है।

उन्होंने अधिकारियों और जवानों से आगे भी सतर्क रहकर राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने को कहा।

कठुआ में कैंसर जागरूकता को बढ़ावा

डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने प्रो. के.बी. अबरोल मेमोरियल कैंसर आउटरीच कैंप का किया उद्घाटन

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जिले में कैंसर जागरूकता और शुरुआती जांच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुप्ता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कठुआ में प्रो. के.बी. अबरोल मेमोरियल कैंसर आउटरीच कैंप आयोजित किया गया। यह कैंप अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट (एएसकॉम्स) जम्मू के सहयोग से लगाया गया। कैंप का उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर सीएमओ कठुआ डॉ. विजय रैना, गुप्ता हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं वरिष्ठ सर्जन डॉ. ए.के. गुप्ता सहित कई वरिष्ठ डॉक्टर और सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। यह कैंप "लाजवंती भगत नाथ रेडिएशंस ऑफ होप" कैंसर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना, समय पर जांच के लिए प्रेरित करना और बेहतर उपचार सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना रहा। एसएमवीडीयू के विद्यार्थियों ने स्वयंसेवक के रूप में सेवाएं देकर कैंप के संचालन में सहयोग किया। कैंप में वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉ. अमित सूरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अविनाश राजरा, ब्रेस्ट ऑनकोप्लास्टिक सर्जन डॉ. सुरभि कुदयार और क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. दीपक अबरोल ने मरीजों को परामर्श और सेवाएं प्रदान कीं।

इस दौरान एलबीएनआरओएच के सचिव शशि खजूरिया, एओआई जम्मू के प्रतिनिधि विगत चंदन और आशुतोष गुप्ता भी मौजूद रहे।

डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता अभियान जिले के दूरदराज क्षेत्रों तक भी पहुंचाए जाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग कैंसर की समय पर जांच और उपचार का लाभ उठा सकें।

कैंप में लोगों को मुफ्त परामर्श, मुफ्त जांच, ट्यूमर मार्कर स्क्रीनिंग और अन्य आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। साथ ही कैंसर जागरूकता संबंधी साहित्य भी वितरित किया गया।

साप्ताहिक राशिफल

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपक. ो निजी जीवन से लेकर करियर–कारोबार तक में उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवेर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज–मस्ती करते हुए बीतेगा। घर–परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर–कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।

वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर–कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल–मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटके कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर–परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन–जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी–साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतरू दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक–कार्यों में खूब रमेगा। किसी धार्मिक–आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक. ाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते–नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ सकती है।

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद–विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर–कारोबार से लेकर घर–परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते–नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी–रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता–सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर–कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर–परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन–पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।

धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और उर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता हैं। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। परीक्षा–प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार–चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर–कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात–व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि. कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर–कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।

कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी–मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल–मिलाप बढ़ेगा। आपके मान–सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी–रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि–भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है।

ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग. लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा–पाठ में बीतेगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

महराजगंज में सीएम योगी ने किया 208 करोड़ की 79 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी का कद बढ़ा गए योगी || यूपी को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बताया || डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों पर दिया जोर- मुख्यमंत्री

सबका जम्मू कश्मीर

महराजगंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। विकास की प्रक्रिया बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके व बिना झुके चलती रहेगी। 2017 के पहले प्रदेश का विकास रुका था। माफिया गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर रहे थे।

सपा, बसपा व कांग्रेस के शासनकाल में अयोध्या में श्रीराम मंदिर व बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। यह पार्टियां कार्य में स्वयं बांधा बनी थी। इसी के चलते पश्चिम बंगाल की जनता ने भी इन्हें उखाड़ फेंका।

मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ शुक्रवार नौतनवां में 208 करोड़ रुपये से अधिक की 79 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते डीजल, पेट्रोल व एलपीजी गैस की सप्लाई पर व्यापक असर पड़ा है। प्रतिदिन भारत सरकार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

उन्होंने कहा कि इस समय विपक्ष के नाकारात्मक नेरेटिव से बचना है। हमें प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहना है। छोटे–छोटे प्रयास कर हम डीजल व पेट्रोल के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। सड़कें बेहतर हुईं हैं। शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुए हैं।

महराजगंज सहित प्रदेश के सभी जिलों में मंदिरों का भी कायाकल्प कराया गया है। पहले यह रुपया कब्रिस्तान के बाउंड्रीवाल के निर्माण के लिए खर्च किया जाता था। पूर्ववर्ती सरकारों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान नहीं दिया। इंसेफलाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में नौनिहाल प्रभावित होते थे। अब डलब इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश नहीं रह गया है। यहां के लोगों को पहचान का संकट नहीं है। देश में सबसे अधिक एक्सप्रेस–वे, मैट्रो, एयरपोर्ट यूपी में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत व नेपाल दोनों मित्र देश के रूप में साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों के बीच रोटी–बेटी का संबंध है। दोनों देशों के बीच बिना किसी बांधा के आवागमन होता है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र का विकास आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि नौतनवां विधानसभा में भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी को पहली बार विजय मिली। उसी कर्ज को चुकाने के लिए जो भी प्रस्ताव यहां के विधायक व सांसद द्वारा दिया जाता है, उसे तत्काल स्वीकृत दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले की सरकारों ने वनटांगिया परिवारों की कभी सुधि नहीं ली, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें भूमि का मालिकाना हक दिलाने के साथ ही सभी अधिकार प्रदान किए।

इससे पहले नौतनवां विधायक ऋषि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया, फरेंदा के पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडेय, जिलाधिकारी गौरव सिंह सोंगरवाल, पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी नौतनवां चेयरमैन बृजेश मणि त्रिपाठी, ब्लाक प्रमुख राकेश मद्धेशिया, वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक बाबा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

कुलदीप कुमार को भाजपा किसान मोर्चा का जिला सचिव बनने पर बधाइयों का तांता

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ (कोटपुन्नू)। भाजपा किसान मोर्चा में कुलद.ीप कुमार को जिला सचिव नियुक्त किए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी नियुक्ति के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों तथा स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुलदीप कुमार लंबे समय से पार्टी की नीतियों को जन–जन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें किसान मोर्चा में जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपना उनके कार्यों और संगठन के प्रति समर्पण का सम्मान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुलदीप कुमार किसानों की समस्याओं और क्षेत्र के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने का कार्य करेंगे। उनकी नियुक्ति से भाजपा किसान मोर्चा को जिला स्तर पर नई मजबूती मिलेगी तथा संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी आएगी।

इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि कुलदीप कुमार पार्टी की नीतियों को गांव–गांव तक पहुंचाने के साथ किसानों के हितों के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। समर्थकों ने खुशी जाहिर की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

Helpline

पुलिस स्टेशन

बाग-ए-बहू	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	2575151
शहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिम्मत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी शहर	2561578
एसपी शहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ

इंडियन एयर लाइन्स	
शहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज़	2453999
सिटी ऑफिस	2573399

रेलवे

रेलवे पूछताछ	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	2470315

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन

बख्शी नगर	2543557
गांधी नगर	2430786
कंपनी बाग	2542582
नया प्लॉट	2573429
पंजतीर्थी	2547537

दूरसंचार विभाग

डायरेक्टरी पूछताछ	197
फॉल्ट रिपेयर	198
ट्रंक बुकिंग	180
बिलिंग शिकायत	2543896

जम्मू नगर पालिका

जं. लाइन्स	2578503
प्रशासन अधिकारी	2542192
स्वास्थ्य अधिकारी	2547440

डाक सेवाएँ

मुख्य डाकघर शहर	2543606
गाँधी नगर	2435863

अग्निशमन सेवाएँ

नियंत्रण कक्ष	101,132, 2476407
शहर	2544263
गाँधी नगर	2457705
नहर	2554064
गंग्याल	2480026

रसोई गैस डीलर

चिनाब गैस	2547633
गुलमौर गैस	2430835
जैकफेड	2548297
एचपी गैस	2578456
शिवांगी गैस	2577020
तवी गैस	2548455

पावर हाउस

गाँधी नगर	2430180
नहर रोड	2554147
जानीपुर	2533828
नानक नगर	2430776
परेड	2542289

सतवारी कैंट	2452813

अस्पताल

जीएमसी अस्पताल	2584290
एस.एम.जी.एस. अस्पताल	2547635
सी.डी. अस्पताल	2577064
डैंटल अस्पताल	2544670
गांधी नगर अस्पताल	2430041
सरवाल अस्पताल	2579402
जी.बी. पंत कैंट अस्पताल	2433500
आयुर्वेदिक कॉलेज	2543661
सी.आर.पी. अस्पताल	2591105
आचार्य श्री चंदर	2662536
मानसिक अस्पताल	2577444
स्वामी विवेकानंद	2547418
ब्लड बैंक	2547637
एम्बुलेंस	2584225, 2575364
एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)	2543739

नर्सिंग होम

मदन अस्पताल	2456727
मेडिकेयर	2435070
त्रिवेणी नर्सिंग होम	2452664
सुविधा नर्सिंग होम	2555965
अल. फिरदौस नर्सिंग होम	2545050
आस्था नर्सिंग होम	2576707
बी एन चैरिटेबल ट्रस्ट	2505310
चोपड़ा नर्सिंग होम	2573580
हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल	2541952
जीवन ज्योति	2576985
युद्धवीर नर्सिंग होम	2547821
मीडियाएड नर्सिंग होम	2466744
सीता नर्सिंग होम	2435007
विभूति नर्सिंग होम	2547969
रामेश्वर नर्सिंग होम	2580601
बी एन चेरिटेबल	2555631
महर्षि दयानंद	2545225

मुस्कान चौरिटेबल ट्रस्ट ने डीआईजी उधमपुर से की मुलाकात, नशा मुक्त अभियान में पुलिस की भूमिका की सराहना

रोहित शर्मा

कटरा, शुक्रवाररू मुस्कान चौरिटेबल ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को डीआईजी उधमपुर शिव कुमार शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा समाज विरोधी गति. विधियों पर अंकुश लगाने हेतु जम्मू–कश्मीर पुलिस की कार्यशैली की सराहना की।

मुस्कान चौरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप मेहरा ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा चलाए जा रहे "नशा मुक्त जम्मू–कश्मीर अभियान" के तहत नशा तस्करों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्रभावी कार्यवाही युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि मुस्कान एनजीओ के सदस्य सदैव जम्मू–कश्मीर पुलिस के साथ खड़े हैं और धर्म नगरी कटरा को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे।

इस अवसर पर एनजीओ के सदस्य मनोहर वज़ीर एवं तेजपाल बक्शी ने भी डीआईजी उधमपुर से मुलाकात कर सामाजिक सरोकारों एवं नशा उन्मूलन अभियान पर अपने विचार साझा।

बॉबिया पहुंचे कमिश्नर सचिव, सीमावर्ती गांवों के विकास कार्यों की समीक्षा

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–।। के तहत योजनाओं के शत–प्रतिशत लाभ पहुंचाने पर जोर

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : योजना, विकास एवं मॉनिटरिंग विभाग की कमिश्नर सचिव आर. एलिस वाज़ ने शुक्रवार को सीमावर्ती गांव बॉबिया का दौरा कर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–।। के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई शिविर लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याएं और विकास संबंधी जरूरतों को सुना।

उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना है। इसके तहत सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और डिजिटल सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

कमिश्नर सचिव ने कहा कि केंद्र और जम्मू–कश्मीर सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने लोगों से विकास कार्यों में प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की। बैठक में अधिकारियों ने बॉबिया और गजनाल गांवों के प्रस्तावित विकास कार्यों की जानक. ारी दी। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा चल रही योजनाओं की भी समीक्षा की गई। डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने बताया कि जिले के छह सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–।। में शामिल किया गया है। इन गांवों के विकास के लिए स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर योजनाएं तैयार की गई हैं।

इस मौके पर हीरानगर के एसडीएम फुलैल सिंह ने सीमावर्ती गांवों की स्थिति और उनके महत्व के बारे में जानकारी।

कठुआ कैंपस में एआई पर विशेष व्याख्यान आयोजित

"ह्यूमन-एआई कम्युनिकेशन का फ्यूचर" विषय पर छात्रों को दी नई तकनीक की जानकारी

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, कठुआ कैंपस, जम्मू यूनिवर्सिटी में "ह्यूमन–एआई कम्युनिकेशन का फ्यूचर" विषय पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉ. शुभनंदन सिंह जमवाल ने छात्रों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और उसके बढ़ते उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आज एआई की मदद से टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, म्यूजिक और कंप्यूटर कोड तैयार किए जा रहे हैं।

उन्होंने चौट जीपीटी, जेमिनी और गिटहब कोपायलट जैसे आधुनिक एआई टूल्स के बारे में भी जानकारी साझा की।

इसके अलावा चौटबॉट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन और डीपफेक डिटेक्शन जैसे एआई के उपयोगों पर भी चर्चा की गई।

डॉ. जमवाल ने एआई से जुड़े खतरों और एथिकल चुनौतियों जैसे गलत जानकारी फैलना, प्राइवेसी वायलेशन, कॉपीराइट और बायस जैसी समस्याओं के प्रति भी जागरूक किया।

कार्यक्रम में कठुआ कैंपस के रेक्टर प्रो. अरविंद जसरोतिया ने कहा कि एआई शिक्षा, रिसर्च और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तेजी से बदलाव ला रहा है।

उन्होंने छात्रों से नई तकनीकों का जिम्मेदारी और सही तरीके से उपयोग करने की अपील की।

इस अवसर पर डॉ. सौरभ शास्त्री ने मुख्य वक्ता का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सनी शर्मा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. प्रणव रत्ता ने प्रस्तुत किया।

वेद मार्ग पर चलकर ही मनुष्य पा सकता है सुख-शांति : स्वामी राम स्वरूप

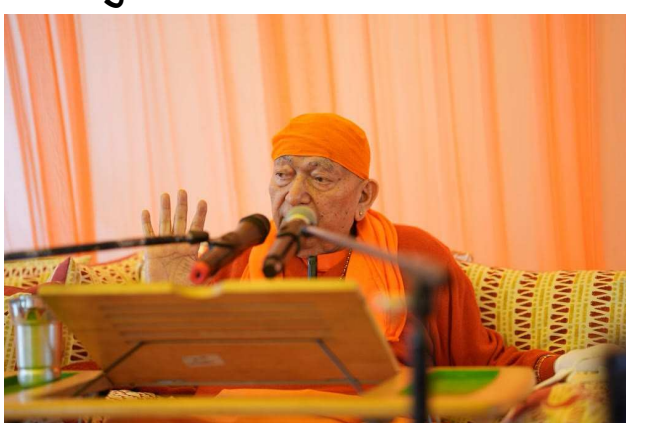

सबका जम्मू कश्मीर

हिमाचल, वेद मन्दिर में चल रहे 78 दिवसीय चारों वेदों के यज्ञानुष्ठान के 33वें दिन स्वामी राम स्वरूप जी, योगाचार्य ने श्रद्धालुओं को वेदों का ज्ञान देते हुए कहा कि केवल प्रार्थना करने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि मनुष्य को शुभ कर्म भी करने चाहिए।

स्वामी जी ने ऋग्वेद मंत्र "भद्रम् नो अपि वातय मनः" का अर्थ समझाते हुए कहा कि मन को कल्याण के मार्ग पर चलाना ही सच्ची उपासना है। उन्होंने बताया कि वेदों में मन को नियंत्रित करने, क्रोध छोड़ने, कटु वचन न बोलने और शुभ कर्म करने का उपदेश दिया गया है।

उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि मनुष्य को वेद मंत्रों का चिंतन करना चाहिए तथा अग्निहोत्र और यज्ञ के माध्यम से परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इससे मन बुरे विच. ारों से दूर होकर धर्म और सदाच. ार की ओर बढ़ता है।

स्वामी राम स्वरूप जी ने कहा कि सुख–शांति, धन–समृद्धि, सुखी गृहस्थ जीवन और मोक्ष प्राप्त करने के लिए यजुर्वेद अध्याय 34 के मंत्रों का अर्थ सहित अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने लोगों को नित्य अग्निहोत्र, यज्ञ और योगाभ्यास करने की प्रेरणा दी।

उन्होंने कहा कि वेद विद्या विद्वान आचार्यों से सीखकर जीवन में अपनाने से मनुष्य अधर्म से दूर रहता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। अंत में उन्होंने लोकवाणी की कहावत "मन जीते जग जीत" का उल्लेख करते हुए कहा कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है।

गद्दी मीरा गोसपाक ग्यारहवीं वाली सरकार मकडोली में 16 मई को विशाल भंडारा

सूफी महफिल, कव्वालियां और अटूट लंगर का होगा आयोजन

राम सिंह

पंजाब। मकडोली में स्थित गद्दी मीरा गोसपाक ग्यारहवीं वाली सरकार दरबार में 16 मई 2026, शनिवार को शनि देव जयंती के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक कार्यक्रम रखे गए हैं।

दरबार के मुख्य सेवादार गुलाम साई बिट्टू शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के दौरान सुबह 10 बजे झंडे की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद सुबह 11 बजे सूफी महफिल और कव्वालियों का आयोजन होगा, जबकि दोपहर 12 बजे से अटूट लंगर बरताया जाएगा।

इस मौके पर इंटरनेशनल गायक कांशी नाथ, सूफी गायक आर. फिरोज और डॉ. राम स्वरूप अपनी हाजरी लगाएंगे। दरबार प्रबंधन की ओर से संगत और श्रद्धालुओं को मेले एवं भंडारे में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करने का निमंत्रण दिया गया है।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

बिलावर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

430 ग्राम हेरोइन बरामद, अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 430 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इस मामले में एक स्थानीय बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में आरोपी के अंत. रराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत भी मिले हैं।

पुलिस के अनुसार 14 मई 2026 को विश्वसनीय सूचना मिलने पर बिलावर थाना पुलिस ने भिन्नी पुल के पास विशेष नाका लगाया। नाके के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। युवक की पहचान मुनीष कुमार पुत्र काला राम निवासी चक दराब खान, कठुआ के रूप में हुई।

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से करीब 15.23 ग्राम चिट्टा और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसके घर में भी भारी मात्रा में नशीला पदार्थ छिपाकर रखा गया है। इसके बाद पुलिस ने अदालत से सर्च वारंट हासिल कर आरोपी के घर पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान घर की एक बंद अलमारी से करीब 415 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया। इस तरह पुलिस ने कुल मिलाकर लगभग 430 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया।

पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और पूरे ड्रग नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं।

कठुआ पुलिस ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा।

कठुआ में फॉरेस्ट विभाग की बड़ी कार्रवाई

अवैध जलाऊ लकड़ी से भरा ट्रक जब्त, तस्करों पर शिकंजा तेज

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : कठुआ फॉरेस्ट डिवीजन ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ अभियान तेज करते हुए एक और बड़ी कार्रवाई की है। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने पंजाब की ओर जा रहे अवैध जलाऊ लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़कर जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार, रेंज ऑफिसर एपीसीपी लखनपुर संजीव सिंह की विजिल टीम ने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अंकित सिन्हा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए ट्रक नंबर श्रज्ञ02ब्ळ–8757 को पकड़ा। ट्रक में अवैध रूप से जलाऊ लकड़ी ले जाई जा रही थी।

फॉरेस्ट विभाग ने बताया कि जम्मू–कश्मीर से बाहर अवैध लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए दिन–रात निगरानी रखी जा रही है। विभाग की टीमें लगातार नाका चेकिंग और गश्त कर रही हैं।

विभाग ने बताया कि 13 मई को भी एक कार्रवाई के दौरान तस्करों ने फॉरेस्ट अधिकारियों की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की थी, जिसमें एक फॉरेस्ट गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कर्मचारी का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में फॉरेस्ट विभाग ने कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं।10 मई को पांच ट्रक जब्त किए गए व 8 मई को दो ट्रक पकड़े गए। 7 मई और 13 मई को भी एक–एक वाहन पकड़ा गया। फॉरेस्ट विभाग ने कहा कि अवैध कटाई और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

बैंक कर्मचारियों के लिए फाइव डे वर्क वीक की मांग तेज

एआईबीओसी ने प्रधानमंत्री से जल्द फैसला लेने की अपील की

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : देशभर के बैंक अधिकारियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) ने बैंकिंग क्षेत्र में फाइव डे वर्क वीक लागू करने की मांग उठाई है। संगठन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में जल्द हस्तक्षेप करने की अपील की है। एआईबीओसी ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो चुकी हैं। यूपीआई, मोबा. इल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और अन्य ऑनलाइन सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। ऐसे में सप्ताह में एक अतिरिक्त दिन बैंक शाखाएं बंद रहने से ग्राहकों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

संगठन के अनुसार फाइव डे वर्क वीक लागू होने से ईंधन की बचत, ट्रैफिक में कमी और बिजली की खपत कम होगी। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। एआईबीओसी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के कार्यालय, आरबीआई, एलआईसी और कई अन्य संस्थानों में पहले से ही पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू है, जबकि बैंकिंग क्षेत्र अभी भी छह दिन की व्यवस्था पर काम कर रहा है। संगठन ने कहा कि इस मुद्दे पर वेतन समझौते के दौरान सिद्धांत रूप में सहमति बन चुकी है। अब केवल सरकार की अंतिम मंजूरी और अधिसूचना जारी होना बाकी है।

एआईबीओसी ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द फैसला लेकर बैंक कर्मचारियों को फाइव डे वर्क वीक की सुविधा देगी।

मानसून से निपटने को प्रशासन तैयार

कठुआ में एडीडीसी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए कठुआ प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (एडीडीसी) सुरिंदर मोहन शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में एडीसी विश्वजीत सिंह, डीटीओ जीवतेज सिंह, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी, हेल्थ, एसडीआरएफ और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एडीडीसी ने सभी विभागों को 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाने और जरूरी सेवाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश, बाढ़ और जलभराव जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह तैयार रहें।

नगर समितियों को नालियों और नालों की सफाई तेज करने को कहा गया ताकि शहरों में पानी जमा न हो। साथ ही बाढ़ संभावित इलाकों की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए।

एसडीआरएफ को बचाव उपकरण और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा गया। रेवेन्यू विभाग को निचले इलाकों के लिए निकासी योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

बसोहली और बिलावर क्षेत्रों में पानी की कमी को देखते हुए जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर भेजने के निर्देश भी जारी किए गए। हेल्थ विभाग को दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने और मेडिकल टीमों को तैयार रखने को कहा गया।

एडीडीसी ने सभी विभागों को आपसी तालमेल बनाए रखते हुए मानसून सीजन के दौरान सतर्क रहने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हीरानगर में कांग्रेस का प्रदर्शन

राज्य का दर्जा बहाल करने और नए राशन कार्ड बनाने की उठाई मांग

सबका जम्मू कश्मीर

हीरानगर : इंडियन नैशनल कांग्रेस की ब्लॉक इकाई हीरानगर द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व्उंत इकनससी के नाम एक लिखित ज्ञापन भी भेजा।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने "हमारी स्टेट, हमारा हक" का नारा लगाते हुए जम्मू–कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 14–15 वर्षों से नए राशन कार्ड नहीं बनाए गए हैं, जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं और जरूरी दस्तावेज बनवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि नए राशन कार्ड जल्द से जल्द जारी किए जाएं। इसके अलावा बैठक में बिजली चोरी, पेपर लीक, गैस और तेल की सप्लाई बहाल करने सहित कई जनसमस्याओं पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए ताकि जनता को राहत मिली।

बमियाल के गांव समराला से लापता महिला की तलाश, सूचना देने वाले को 50 हजार रूपये इनाम

गुमशुदा की तलाश

राज कुमारी

पत्नी **सतीश कुमार उर्फ सोनू**

गांव सरमाला/जन्याल
पोस्ट ऑफिस जन्याल
ब्लॉक बमियाल
जिला व तहसील पठानकोट

₹ 50,000 का नगद इनाम दिया जाएगा

पता देने वाले को

संपर्क मोबाईल नंबर
9622258668, 9186171300
8968336267

कृपया सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।
आपकी छोटी सी मदद किसी के परिवार को मिल सकती है।

सबका जम्मू कश्मीर

पठानकोट/पंजाब : पठानकोट जिले की तहसील बमियाल के गांव समराला/जन्याल निवासी राज कुमारी पत्नी सतीश कुमार उर्फ सोनू बीती 21 तारीख से लापता हैं।

बताया जा रहा है कि राजकुमारी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थीं, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटीं। देर शाम तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

परिजनों के अनुसार राजकुमारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और वह पहले भी एक बार घर से चली गई थीं, हालांकि उस समय उन्हें ढूंढ लिया गया था। इस बार परिवार ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में लगातार तलाश की, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

राजकुमारी के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से अपील की कि यदि किसी को राजकुमारी के बारे में कोई जानकारी मिले तो दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें।

उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोप. नीय रखा जाएगा।

परिवार की ओर से राजकुमारी का पता बताने वाले को 50 हजार रुपये नकद इनाम देने की घोषणा भी की गई है।

राज कुमारी का पता :

गांव सरमाला/जन्याल, पोस्ट ऑफिस जन्याल, ब्लॉक बमियाल, जिला व तहसील पठानकोट। संपर्क नंबर : 9622258668, 9186171300, 8968336267.

कठुआ में फॉरेस्ट विभाग की बड़ी कार्रवाई

अवैध जलाऊ लकड़ी से भरा ट्रक जब्त, तस्करों पर शिकंजा तेज

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जिले में बढ़ते नशे (चिट्टा) और प्रदूषण की समस्या को लेकर "एंटी पॉल्यूशन मूवमेंट, कठुआ" ने चिंता जताई है। संगठन ने कहा कि नशे की लत लगातार युवाआ. की जिंदगी बर्बाद कर रही है, जबकि बढ़ता प्रदूषण मानव जीवन, खेती और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है।

संगठन के अनुसार "एंटी पॉल्यूशन मूवमेंट" वर्ष 2006 से प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। वर्ष 2007 में यह मामला प्रदूषण समिति में भी उठाया गया था, जिसके बाद कुछ राहत मिली थी।

संगठन ने बताया कि 7 मई 2026 को हटली मोड़, कठुआ में एक दिवसीय धरना देकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया था।

इसी मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए 19 मई 2026 को शाम 5 बजे शास्त्री नगर, कठुआ स्थित श्री अशफाक अहमद चौहान के निवास पर एक जरूरी बैठक बुलाई गई है।

संगठन ने समाज के जागरूक नागरिकों से बैठक में शामिल होकर सहयोग देने की अपील की है। इस अवसर पर आई. डी. खजूरिया ने कहा कि समाज और युवाओं को बचाने के लिए सभी लोगों को मिलकर आगे आना होगा।

भीम आर्मी ने बच्चों को भेंट किए वॉलीबॉल, खेलों के प्रति किया प्रेरित

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : भीम आर्मी भारत एकता मिशन जम्मू–कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार लोनी गुरुवार को अपने साथियों के साथ पंचायत हमीरपुर के गांव पलाई पहुंचे। इस दौरान उनके साथ तहसील अध्यक्ष मढ़ीन करण कुमार और जिला कठुआ प्रभारी लखी कुमार भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान गांव में खेल रहे बच्चों को वॉलीबॉल भेंट किए गए और बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक व प्रेरित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार लोनी ने कहा कि बच्चों और युवाओं को शिक्षा, खेल और जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ाना समाज के विकास के लिए बेहद जरूरी है।

वॉलीबॉल मिलने पर बच्चों ने खुशी जताई और इस सहयोग के लिए पवन कुमार लोनी तथा भीम आर्मी टीम का धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा कि भीम आर्मी हमेशा समाज के बच्चों और युवाओं को शिक्षा, खेल और जागरूकता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करती रहेगी। इस मौके पर "जय भीम, जय भारत, जय संविधान" के नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

नाम का सुमिरन ही सभी रोगों की दवा: सद्गुरू श्री मधुपरमहंस जी महाराज

अखनूर में प्रवचन के दौरान कहा– मन और इंद्रियों पर नियंत्रण से मिलता है सच्चा सुख

सबका जम्मू कश्मीर

अखनूर, जम्मू : साहिब बंदगी के सद्गुरु श्री मधुपरमहंस जी महाराज ने अखनूर में आयोजित सत्संग में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी रोगों की सबसे बड़ी दवा नाम का सुमिरन है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सबसे अधिक दुख इंद्रियों और मन के कारण मिलता है। शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार ही दुख और रोगों का कारण बनते हैं।

उन्होंने कहा कि संतों ने हमेशा नाम की शरण में जाने का संदेश दिया है। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो मनुष्य को परमात्मा के नाम का सुमिरन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा साधु कहलाता है।

सद्गुरु महाराज ने कहा कि आज के समय में पारिवारिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पहले भारत में संयुक्त परिवार की मजबूत व्यवस्था थी, जिसे ऋषि–मुनियों ने बनाया था, लेकिन अब परिवारों में अलगाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि धन–दौलत होने के बावजूद यदि घर में शांति नहीं है तो जीवन दुखमय बन जाता है।

उन्होंने कहा कि मन हमेशा आत्मा को भटकाने का काम करता है। जब भी व्यक्ति ध्यान लगाने बैठता है तो मन उसे इधर–उधर भटकाने लगता है। इसलिए ध्यान को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। सभी धर्म और मत यही कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन एकाग्र ध्यान से ही संभव है।

उन्होंने बताया कि मन एक समुद्र की तरह है, जिसमें इच्छाओं की लहरें लगातार उठती रहती हैं। जब तक मनुष्य अपने ध्यान को एकाग्र नहीं करेगा, तब तक उसे आत्मिक सुख और भीतर का अनुभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि संसार के सुख कुछ समय बाद दुख में बदल जाते हैं, जबकि आत्मा का सुख हमेशा स्थायी और आनंदमयी होता है।

NOTICE

This is to inform the general public that Mr. Asha Ram alias Ashya Kumar, S/o Sh. Darbari Lal, R/o Goond, Tehsil Nagri Parole, District Kathua, is one and the same person. In all official and personal documents, including Aadhaar Card, the name is recorded as Asha Ram. The applicant has requested that the same name be reflected uniformly in all concerned records and license documents to avoid any confusion in future. If any person has any objection regarding the above-mentioned name clarification/correction, he/she may contact the undersigned within 7 days from the publication of this notice.

Deponent
Asha Ram alias Ashya Kumar
R/o Goond, Tehsil Nagri Parole
District Kathua
Date: 06-03-2026

NOTICE

This is to inform the general public that I, Daljit Singh S/o Tripat Singh, R/o Village Mirpur Jagoo, Tehsil Nagri Parole, District Kathua, am the same person whose name has been mistakenly recorded as "Daljeet Singh" in the Registration Certificate (R.C.) of vehicle bearing No. JK08E-2028. My correct name, as mentioned in my Aadhaar Card and other official documents, is "Daljit Singh". The difference in the name is only due to a spelling mistake and both names refer to one and the same person. Any person having any objection regarding this correction may contact the undersigned within 7 days from the date of publication of this notice, failing which no objection shall be entertained thereafter.

Name: Daljit Singh S/o Tripat Singh
Address: Village Mirpur Jagoo, Tehsil Nagri Parole, District Kathua

Date: _____
Signature: _____

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ पहुंचे मंडलायुक्त रमेश कुमार, एक्सप्रेस-वे और अमरनाथ यात्रा तैयारियों की समीक्षा

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ। रमेश कुमार ने गुरुवार को कठुआ जिले का दौरा कर कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नशा मुक्त जम्मू–कश्मीर अभियान, श्री अमरनाथ जी यात्रा (संजय)–2026 की तैयारियों और आधारभूत ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने दिल्ली–अमृतसर– कटड़ा एक्सप्रेस–वे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अलग–अलग हिस्सों में चल रहे काम की प्रगति देखी। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक कर परियोजना को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया।

इसके अलावा उन्होंने लखनपुर कॉरिडोर का दौरा कर सौंदर्यीकरण, ट्रैफिक मैनेजमेंट और यात्रियों के लिए सुविधाओं के सुधार कार्यों की समीक्षा की। यह कार्य आगामी अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं।

मंडलायुक्त ने जिले में राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) तथा 1947, 1965 और 1971 के विस्थापित परिवारों के स्वामित्व मामलों की प्रगति भी जांची। उन्होंने लंबित मामलों को जल्द निपटाने और डाटा एंट्री में किसी भी प्रकार की गलती न होने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

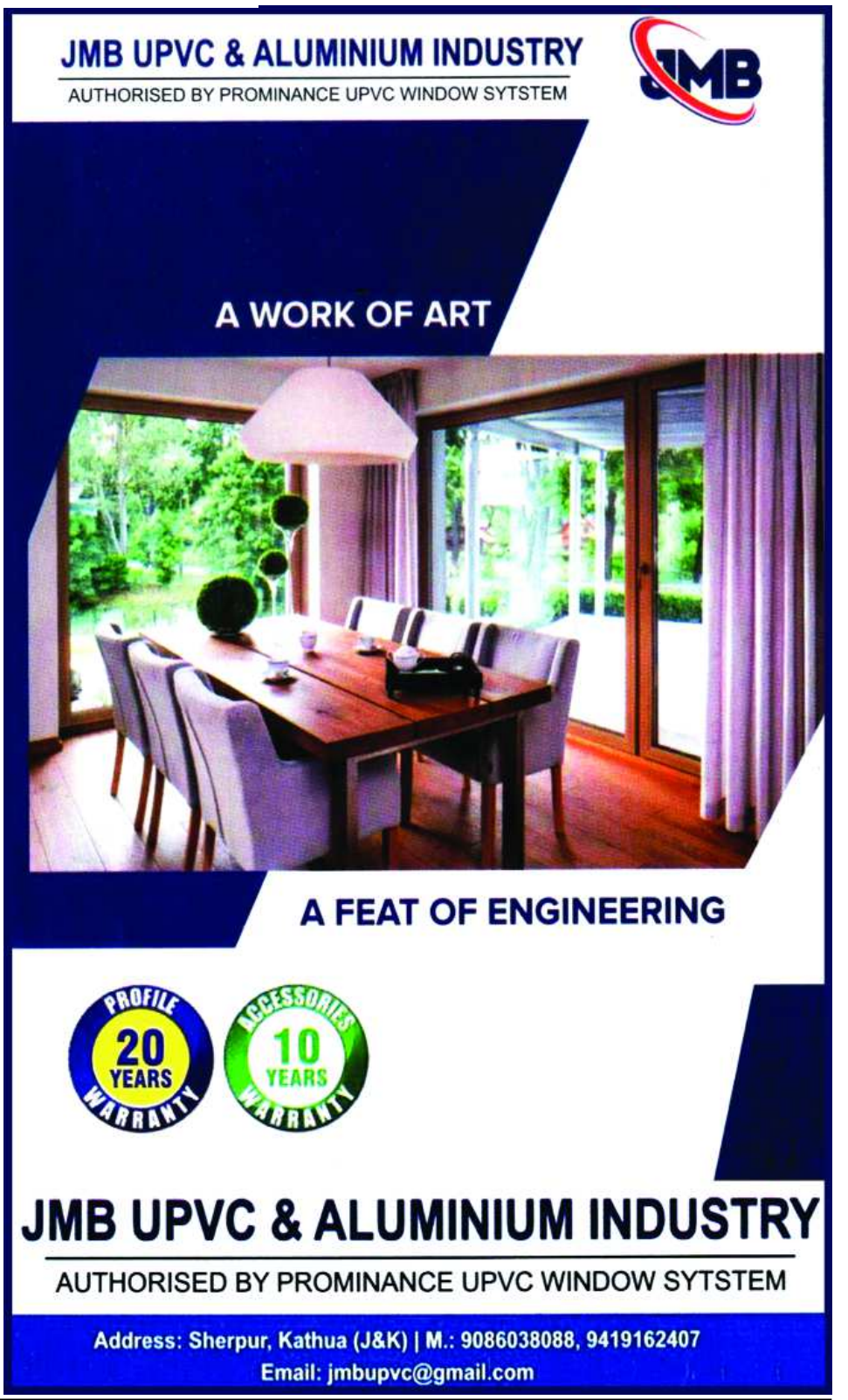

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशकः राज कुमार द्वारा एम/एस डी. आर प्रिंटिंग प्रेस, बैन बजाल्ता, तहसील जम्मू से मुद्रित एवं नगरी पैरोल नगरी, जिला कठुआ, जम्मू और कश्मीर पिन.कोड नंः 184151 । संपादकः राज कुमार